जबलपुर गुरुवार 10 सितंबर 2026 > शक संवत 1948, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी

वर्ष 32 अंक 73 मूल्य ₹ 3.00 > पेज 08 > आर.एन.आई. पंजीयन नम्बर 64561/96

www.swatantramat.com

अब हर रोज दर्पण

▶▶ 3

स्वतंत्र मत

स्वतंत्र मत में विज्ञापन देने के लिए 9589920250 पर कॉल करें * स्वतंत्र मत का अंक प्राप्त करने के लिए 9301359695 पर कॉल करें।

मौसम

अधिकतम तापमान 33.0°C

न्यूनतम तापमान 23.1°C

सूर्योदय - 5.56 | सूर्यास्त - 6.19

आखिर युवाओं के बीच क्यों नहीं चमक पा रहे ... ▶▶ 4

मिर्जापुर- द मूवी: लेखक और निर्देशक को था... ▶▶ 5

गांवों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं... ▶▶ 7

राहुल गांधी ने सांसद निधि के कार्यों का किया लोकार्पण

रायबरेली (वार्ता)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के स्थानीय सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को अपने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन बुधवार को भुएमऊ स्थित आवास पर सांसद निधि से कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। उनके सेंट्रल बार एसोसिएशन और चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि श्री गांधी मंगलवार शाम यहां दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। उन्होने देर शाम प्रभु टाउन में स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके समाधान को लेकर चर्चा की थी।

तेलंगाना विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा

हैदराबाद (वार्ता)। तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। बीआरएस सदस्यों ने न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 22 सदस्यों को मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बीआरएस सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कार्यवाही बाधित हुई। इसके बाद विधायी मामलों के मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू ने सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर अध्यक्ष ने 22 सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया।

कदापि नहीं छोड़ेगी सरकार 'अवैध-शराब' के गुनहगार

मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करने प्रशासन को दी खुली छूट

भोपाल (स्वतंत्र मत)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब से लोगों की हुई मृत्यु के प्रकरण में कठोरतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाए। जिले में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज सागर के बुन्देलखंड मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन अपराध और असामाजिक गतिविधियों के प्रति जीरो

टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के साथ-साथ आस-पास और सीमावर्ती क्षेत्रों में गहन जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी शंका या संदिग्ध गतिविधि की गुंजाइश हो, वहाँ तत्परता से पड़ताल की जाए और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को कहा कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से सोशल मीडिया या अन्य विभिन्न माध्यमों पर अनावश्यक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखने और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में नशा विरोधी अभियान को गति देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए। साथ ही, नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर जनजागरूकता और नशा मुक्ति के प्रभावी कार्यक्रम संचालित किए जाएं।

प्रदेश में कठोर कानून का है प्रावधान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार के रहते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय कठोर कानून बनाया गया कि इसमें धारा 49 और बाकी 304 जोड़ते हुए हत्या से लेकर आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा देने का प्रावधान है। इस प्रकार की घटना में लिप्त है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रशासन को फ्री हैंड दिया है कि वह उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिनके अवैध अतिक्रमण हैं या अलग से किसी ने इस प्रकार से अपना साम्राज्य चलाया है, उस पर भी काम करें। हमने पूरे राज्य में निर्देश जारी किए हैं कि नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए धार्मिक संस्थाओं के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ अलग-अलग स्तर पर शासन की ओर से भी नशा मुक्ति के अभियान चलाने की आवश्यकता है। हम सबको इससे निपटने के लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रतिबद्धता की जरूरत पड़ेगी।

अस्पताल में प्रभावितों का जाना हाल

बंडा के अवैध शराब मामले के प्रभावितों को त्वरित राहत देने और उनका ढांढस बंधाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम जाना और पीड़ित परिवारों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने परिजन से कहा कि सरकार हर स्थिति में आपके साथ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रत्येक मरीज के पास जाकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति देखी। पीड़ितों के परिजनों से पूछा-परिवार में कौन-कौन है? चिंता मत करिए, सरकार हर स्थिति में आपके साथ खड़ी है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बीएमसी के प्रभारी डीन, अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सकों से पीड़ितों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही आवश्यक दवाओं, टेस्ट और विशेषज्ञों की तैनाती 24 घंटे सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट में घिरे ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट

छात्र को नोटिस भेजने पर सीजेआई ने लगाई फटकार

भोपाल (स्वतंत्र मत)

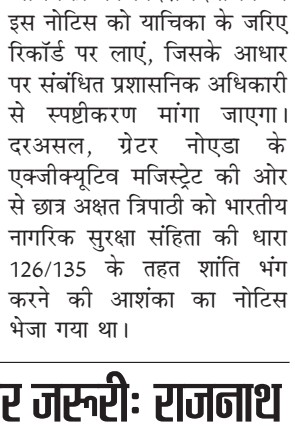

ग्रेटर नोएडा के एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रचार कर रहे लॉ के एक छात्र को नोटिस भेजने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस कार्रवाई को बेहद गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट की भूमिका पर कड़े सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, स्थानीय प्रशासन की ओर से इस नोटिस को वापस ले लिया गया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे एक गंभीर विषय माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब 1 सितंबर के अपने देशव्यापी आदेश में छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दण्डात्मक कार्रवाई पर स्पष्ट रोक लगा दी गई थी, तो ऐसे में कोई अधिकारी उसका उल्लंघन कैसे कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत भट्टाचार्य ने इस मुद्दे को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के समक्ष उठाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई ने कहा, कोई मजिस्ट्रेट ऐसा नोटिस जारी करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? हमने साफ निर्देश दिया था कि किसी भी छात्र के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या दण्डात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। देश का कोई भी मजिस्ट्रेट शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। अदालत में एडवोकेट भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि पुलिस की रिपोर्ट पर ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट ने द्वितीय वर्ष के कानून के छात्र अक्षत त्रिपाठी को नोटिस दिया था। भले ही बाद में इसे वापस ले लिया गया हो, लेकिन यह छात्रों के मन में भय का माहौल पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर अदालत की अवहेलना करार दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सवाल किया कि जब नोटिस वापस ही ले लिया गया है, तो इस मामले में अब क्या कार्रवाई बचती है? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अवहेलना का अपराध एक बार पूरा हो जाने के बाद महज नोटिस वापस ले लेने से समाप्त नहीं हो जाता। यह देश की सर्वोच्च अदालत की गरिमा और लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर सीजेआई ने अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे इस नोटिस को याचिका के जरिए रिकॉर्ड पर लाएं, जिसके आधार पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। दरअसल, ग्रेटर नोएडा के एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ओर से छात्र अक्षत त्रिपाठी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126/135 के तहत शांति भंग करने की आशंका का नोटिस भेजा गया था।

कभी सफल नहीं होगी कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश: सुरजेवाला

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई कर रही है। श्री सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शुरू किया गया यह राजनीतिक उत्पीड़न कोई नयी कहानी नहीं है और इससे कांग्रेस नेता न तो डरेंगे और न ही कन्नड़ जनता की सेवा से पीछे हटेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं कांग्रेस नेता सतीश जरकीहोली के खिलाफ लगातार राजनीतिक कार्रवाई और छापेमारी भाजपा की राजनीतिक बदले की भावना का एक और उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों में भाजपा और जनता दल द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गयी कार्रवाइयों की लंबी सूची खुद पूरी कहानी बयां करती है। श्री सुरजेवाला ने कहा कि ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उनके भाई डी.के. सुरेश, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, तत्कालीन मंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, मंत्री बी.जेड. जमीर अहमद खान,

सांसद ई. तुकाराम, तत्कालीन मंत्री बी. नागेंद्र, विधायक बसनगौड़ा दद्दाल, सतीश सैल, एन.ए. हारिस, नारा भरत रेड्डी, एस.एन. सुब्बा रेड्डी और के.सी. वीरेंद्र के खिलाफ छापेमारी की। उन्होंने सवाल उठाया कि दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, भाजपा नेता रेणुकाचार्य और जनार्दन रेड्डी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का मामला कर्नाटक के राज्यपाल के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर ने पूरा वंदे मातरम गाया

श्रीनगर। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस पर उमर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि गठबंधन के सहयोगियों पर शर्तें थोपने का अधिकार कांग्रेस का नहीं है। वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस को 'मुस्लिम लीग' की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। विवाद सोमवार को जम्मू-कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राष्ट्रीय गीत का पूरा संस्करण गाए जाने के बाद शुरू हुआ।

सुरक्षित समुद्री मार्ग और निर्बाध व्यापार जरूरी: राजनाथ

नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिन्द महासागर क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, नौवहन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान और निर्बाध समुद्री व्यापार को जरूरी बताते हुए भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को उभरती समुद्री चुनौतियों के गंभीर खतरा बनने से पहले उनसे मिलकर निपटने के लिए नए प्रोटोकॉल, कौशल और अनुभव साझा करने होंगे। श्रीलंका यात्रा पर गये श्री सिंह ने बुधवार को वहां रक्षा मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के घटनाक्रमों के प्रति दोनों देश उदासीन नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण और संयुक्त अभ्यासों के जरिए दोनों देशों ने अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं लेकिन रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को, खासकर समुद्री क्षेत्र में, और मजबूत करने की जरूरत है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और श्रीलंका साझा समुद्र से जुड़े हैं और समुद्री सुरक्षा दोनों देशों के व्यापार, सुरक्षा और भविष्य को प्रभावित करती है। उन्होंने खोज एवं बचाव अभियानों में दोनों

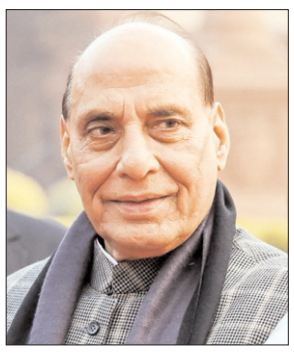

देशों के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे समुद्र में कई लोगों की जान बचाई गई है। दोनों देश मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री डकैती और मानव तस्करी से निपटने में भी सहयोग कर रहे हैं।

कक्षा 6 के स्टूडेंट्स को तीन-भाषा नीति से छूट मिले: सुको

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि वह इस शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 के छात्रों को तीन-भाषा नीति से छूट देने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि अगर संभव हो तो इस साल के छात्रों के लिए कुछ राहत दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 17 सितंबर तक टाल दी। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिया।

सूचना

स्वतंत्र मत के समस्त प्रतिनिधियों, पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं को सूचित किया जाता है कि तकनीकी कारणवश स्वतंत्र मत का आज का अंक 08 पृष्ठों का ही प्रकाशित हो सका है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। - संपादक

आतंकी उमर नबी ही था लाल किला ब्लास्ट का मास्टरमाइंड

नई दिल्ली। दिल्ली में नवंबर 2025 में लाल किले के पास कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड आतंकी उमर उन नबी ही था। एनआईए ने बुधवार को चार्जशीट में ये जानकारी दी। धमाके वाली कार को नबी खुद चला रहा था। ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई थी। नबी उर्फ पिंडा और राहुल भट 2022 की शुरुआत से निष्क्रिय हो चुके अंसार गजवत-उल-हिंद मॉड्यूल को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इस मॉड्यूल को अल-कायदा इन द इंडियन सब-कॉन्टिनेंट से जुड़े नए रूप के तौर पर बताया गया है। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास शाम करीब 6:50 बजे हुए कार ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत और 29 लोग घायल हुए थे।एजेंसी ने कहा है कि नबी और मॉड्यूल के दूसरे सदस्यों के पास ऐसा कट्टरपंथी साहित्य था और वे उसे आपस में शेयर करते थे, जिसमें हथियारबंद संघर्ष और हिंसा की वकालत की गई थी। जांच में डेफिनिशन ऑफ जिहाद, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जिहाद, द 21 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जिहाद, 39 वेज टू सर्व एंड पार्टिसिपेट इन जिहाद और 44 वेज टू सपोर्ट जिहाद नाम के दस्तावेजों की जांच की गई।

दिल्ली में अवैध निर्माण वाली इमारतों पर बुलडोजर चलेगा

नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन मे पीजी बिल्डिंग गिरने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए हैं। सीएम ने को अवैध पीजी हॉस्टलों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं, दिल्ली नगर निगम ने पीजी बिल्डिंग के पास की इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। इन इमारतों में गर्ल्स पीजी था। लड़कियां पीजी खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं। मंगलवार तक 24 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई और 7 अवैध ढांचों को सील किया जा चुका था। सत्य निकेतन में 6 सितंबर को पांच मंजिला पीजी बिल्डिंग गिरने से 7 लोगों की मौत हुई थी। मामले में बुधवार तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

4 राज्यों के रेल-खंडों पर बढ़ेगी पटरियों की संख्या

नई दिल्ली

सरकार ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने की कुल 540 किलोमीटर लंबी पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी जिन पर कुल अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपये आयेगी। इन परियोजनाओं में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली अरक्कोनम - रेणिगुंटा तीसरी और चौथी लाइन (77 किलोमीटर), कर्नाटक में व्हाइटफील्ड- बंगारपेट तीसरी और चौथी लाइन (47 किलोमीटर), तमिलनाडु में होसुर-ओमलूर मार्ग के दोहरीकरण (147 किलोमीटर), तमिलनाडु में सलेम-करूर-डिंडीगुल दोहरीकरण (159 किलोमीटर) और तेलंगाना में सिकंदराबाद (घाटकेसर)-काजीपेट बहु-पटरीकरण (110 किलोमीटर) की परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति में लिए गये इन निर्णयों की जानकारी सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी । इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है जिससे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करने वाली ये पांच परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर की वृद्धि करेंगी। स्वीकृत मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 2,121 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं कुल 11000 किलो मीटर तक फैले सात उच्च व्यस्त रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने के सरकार की वृहद योजना का हिस्सा हैं। इन में 2000 किलोमीटर रेल मार्गों को चार लेन का बना दिया गया है। 5000 किलोमीटर के मार्गों की परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। 4000 किलोमीटर मार्ग पर नयी लाइनें बिछाने काम चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। सीसीईए ने आज ही झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को जोड़ने वाली वाली तीन परियोजनाएं भी शामिल हैं जिनसे मौजूदा रेल नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर - झारसुगुड़ा (बागदेही) चौथी लाइन, कटनी - पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर (उसलापुर) - पेंड्रा रोड के बीच तीसरी लाइन की परियोजना शामिल है। इन तीन परियोजनाओं

पर कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

रेल मंत्री ने कहा कि इन रेल लाइनों की क्षमता बढ़ने से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवाओं की विश्वसनीयता बेहतर होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को जोड़ने वाली उपरोक्त पांच परियोजनाओं के चालू होने पर लगभग 2,121 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिनकी कुल आबादी लगभग 52 लाख है। इन मार्गों की क्षमता बढ़ने से तिरुपति, सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर (तिरुत्तानी), श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर (तिरुचानूर), कोटिलिंगेश्वर देवालय, श्री सीथी बैरवेश्वर स्वामी मंदिर, बंगारू तिरुपति, कोलार गोल्ड फील्ड्स, होगेनक्कल जलप्रपात, होसुर किला, मेट्टूर बांध, कोडाइकनाल की पहाड़ियां, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य, नामक्कल अंजनेयर मंदिर, नामक्कल किला, कल्याण पसुपतीश्वर मंदिर, यादाद्रिगुट्टा मंदिर, भोंगीर किला, सुरेंद्रपुरी और स्वर्णगिरि मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन के महत्व के स्थलों के लिए आवागन की सुविधा भी बढ़ेगी।

4.7 करोड़ टन प्रति वर्ष माल ढुलाई की संभावना

मंत्री ने बताया कि ये परियोजनाएं कोयला, सीमेंट, लौह एवं इस्पात, कंटेनर, ऑटोमोबाइल, खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक आदि वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर हैं। क्षमता बढ़ाने के इन कार्यों से अतिरिक्त 4.7 करोड़ टन प्रति वर्ष माल ढुलाई की संभावना है। उन्होंने कहा कि रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन माध्यम है। इसलिए इन परियोजनाओं से देश के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, लगभग आठ करोड़ लीटर तेल के आयात में कमी आएगी और लगभग 42 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा जो लगभग दो करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

धान फर्जीवाड़े में 10 आरोपितों पर 1.39 करोड़ की वसूली फिर भी न राशि जमा हुई न तहसील कोर्ट में पहुंचे

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

मझौली तहसील के ग्राम हटोली में धान खरीदी के दौरान सामने आए बड़े फर्जीवाड़े में प्रशासन की कार्रवाई और वसूली की प्रक्रिया पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्राम संकुल स्तरीय संगठन में स्टाक सत्यापन के दौरान करीब 5 हजार 302 क्विंटल धान की कमी सामने आने के बाद समिति प्रबंधक, अध्यक्ष, सचिव सहित 10 लोगों को मुख्य आरोपित बनाकर एफआइआर दर्ज की गई थी। जांच में सामने आई कमी की कुल राशि करीब एक करोड़ 39 लाख 19 हजार रुपये आंकी गई है। इसी आधार पर मझौली तहसीलदार ने 10 आरोपितों में राशि बराबर बांटते हुए प्रत्येक के खिलाफ करीब 13 लाख 91 हजार 906 रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया था। नोटिस में सात दिन के भीतर राशि जमा करने के निर्देश थे, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी किसी आरोपित ने राशि जमा नहीं की। इतना ही नहीं, आरोपित तहसील कोर्ट में पेशी के लिए भी नहीं पहुंचे। अब प्रशासन ने मंगलवार को दोबारा नोटिस जारी कर राशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

5302 क्विंटल धान की कमी से खुला मामला

पिछले वर्ष हुई धान खरीदी में मझौली क्षेत्र के ग्राम हटोली स्थित ग्राम संकुल स्तरीय संगठन में स्टाक सत्यापन के दौरान बड़ी मात्रा में धान की कमी सामने आई थी। जांच में करीब 5 हजार 302 क्विंटल धान कम पाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में धान के स्टाक में अंतर मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कराई। जांच आगे बढ़ने के साथ समिति और उपार्जन व्यवस्था से जुड़े कई लोगों की भूमिका सामने आई। इस मामले में पहले 10 लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई और करीब एक माह बाद एक अन्य आरोपित के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया। प्रशासन अब गायब पाए गए धान की कीमत की वसूली की कार्रवाई कर रहा है।

10 आरोपितों में बराबर बांटी वसूली की राशि

तहसील स्तर पर की गई वसूली कार्रवाई में करीब एक करोड़ 39 लाख 19 हजार रुपये की राशि को 10 आरोपितों के बीच बराबर बांटा गया। इसके अनुसार प्रत्येक आरोपित के हिस्से में 13 लाख 91 हजार 906 रुपये की राशि आई। मझौली तहसीलदार की ओर से जारी नोटिस में आरोपितों को नोटिस जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन के अनुसार यह अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी आरोपित ने राशि जमा नहीं की। मामले में खास बात यह भी रही कि जिन आरोपितों को तहसील कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना था, वे वहां भी पेश नहीं हुए। इससे वसूली प्रक्रिया को लेकर प्रशासन के सामने अगली कार्रवाई का सवाल खड़ा हुआ है। प्रशासन के अनुसार नोटिस जारी होने के बाद 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी आरोपित ने निर्धारित राशि जमा नहीं की है। राशि जमा नहीं करने के साथ ही आरोपितों के तहसील कोर्ट में उपस्थित नहीं होने को भी गंभीरता से लिया गया है। मंगलवार को तहसीलदार ने सभी 10 आरोपितों के खिलाफ फिर से नोटिस जारी किए। इस बार उन्हें राशि जमा करने के लिए सात दिन के बजाय 15 दिन का समय दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मझौली तहसीलदार जनकी उइके के अनुसार, सभी 10 आरोपितों को दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 15 दिन का समय दिया गया है। एक सितंबर तक राशि जमा किया जाना था, लेकिन अब तक किसी ने भी राशि जमा नहीं की है।

दो अधिकारियों को सेवा से भी पृथक किया

धान खरीदी से जुड़े इस मामले में केवल समिति स्तर के लोगों पर ही कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को भी आरोपित बनाया गया है। उपार्जन केंद्र के नोडल अधिकारी आनंद भारसाकले और प्रभारी ब्लाक प्रबंधक प्रकाश पांडे को भी प्रकरण में आरोपित बनाया गया है। इन दोनों के खिलाफ भी 13 लाख 91 हजार 906 रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दोनों को सेवा से पृथक किए जाने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। प्रभारी ब्लाक प्रबंधक प्रकाश पांडे के खिलाफ करीब 13 लाख 91 हजार रुपये की वसूली का नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

हनुमानताल क्षेत्र में मिला बच्चे का शव, मोतीनाला प्रसूतिका गृह के समीप घटना से सनसनी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जबलपुर में हनुमानताल क्षेत्र के चार खम्बा क्षेत्र में आज उस वक्त सनसनी फैल गई। जब लोगों ने सड़क किनारे एक चार माह के मासूम बच्चे का शव देखा। शव मिलने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, जिनके बीच तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त रही। पुलिस के अनुसार हनुमानताल के चार खम्बा क्षेत्र में शाम 4 बजे के लगभग लोगों की आवाजाही लगी रही, इस बीच कुछ लोगों की नजर सड़क किनारे पड़े बच्चे पर पड़ी तो ठिठक गए। उन्होने करीब जाकर देखा तो आसपास के लोगों को बताया, देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूछताछ के बाद शव को उठाकर मेडिकल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर मोतीनाला प्रसूतिका गृह है, इस तरह की घटना जांच का विषय है। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज निकाले जा रहे है, ताकि मामले का खुलासा हो सके।

एक ही कमरे में चल रही थीं तीन-तीन कक्षाएं, तीन में से दो शिक्षक मिले गायब

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने के दावों के बीच नुनसर के एक सरकारी स्कूल की स्थिति ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक ही कमरे में तीन कक्षाओं के बच्चों को बैठाकर एक शिक्षिका पढ़ाती मिलीं।

निरीक्षण के दौरान जब अधिकारियों ने इसकी वजह जानी तो सामने आया कि स्कूल में पदस्थ तीन शिक्षकों में से एक शिक्षिका मातृत्व अवकाश पर हैं, जबकि दूसरे शिक्षक की ड्यूटी साक्षरता अभियान में लगी हुई है। नतीजा यह रहा कि एक शिक्षिका के भरोसे तीन कक्षाओं की पढ़ाई चल रही थी। शिक्षकों की कमी को लेकर पूछताछ हुई तो पता चला कि यह स्थिति कुछ दिनों की नहीं,

बल्कि लंबे समय से बनी हुई है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों तक मामला पहुंचा और स्कूल में शिक्षण व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश जारी किए गए। साक्षरता अभियान के साथ स्कूल की जिम्मेदारी मामले में भास्कर गुप्ता प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद का प्रभार प्राप्त, एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला उजरोड़ को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साक्षरता मिशन से जुड़े कार्यों के साथ मूल विद्यालय के शैक्षणिक दायित्व का भी समुचित निर्वहन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्थिति में साक्षरता अभियान के कारण विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। निर्देशों के अनुसार संबंधित शिक्षक अब सप्ताह में केवल दो दिन साक्षरता अभियान के कार्य में रहेंगे, जबकि चार दिन मूल स्कूल में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों ने निर्देशित किया कि भविष्य में विद्यालयीन कार्य प्रभावित होने अथवा इस संबंध में शिकायत मिलने पर संबंधित शिक्षक और संस्था प्रभारी की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई जाएगी।

इटारसी की किन्नरों का जबलपुर स्टेशन पर हंगामा यात्रियों से विवाद, जीआरपी ने 3 को पकड़ा

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

रेलवे स्टेशन जबलपुर में यात्रियों के साथ विवाद कर शांति भंग करने वाले किन्नरों के विरुद्ध शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पकड़ी गई तीनों किन्नर इटारसी की हैं और जबलपुर स्टेशन पर उत्पात मचा रही थीं। जीआरपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन जबलपुर के प्लेटफार्म नंबर 1 पर किन्नरों द्वारा आने-जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों के साथ अभद्रता एवं गाली-गलौज करते हुए विवाद किया जा रहा था। उक्त व्यक्तियों द्वारा समझाइश देने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा थे तथा विवाद कर शांति भंग करने की स्थिति निर्मित कर रहे थे। मौके पर थाना जीआरपी जबलपुर पुलिस स्टाफ द्वारा पहुंचकर उन्हें समझाइश दी गई, किंतु उनके द्वारा समझाइश नहीं मानी गई। संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण स्थिति बनने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरोपी बबली किन्नर, गुरु रेशम खान उम्र 45 वर्ष, निवासी इटारसी, जिला नर्मदापुरम, कुसुम कुमारी गुरु रेशम खान उम्र 25 वर्ष निवासी निरानू मस्जिद के पास नाला मोहल्ला इटारसी थाना इटारसी जिला नर्मदापुरम तथा मनू किन्नर गुरु रेशमा खान उम्र 20 वर्ष निवासी निराद मस्जिद के पास नाला मोहल्ला इटारसी थाना इटारसी जिला नर्मदापुरम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126(बी), 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए इस्तगासा तैयार कर माननीय एसडीएम महोदय, रांझी, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माता गुजरी कॉलेज की प्रोफेसर के साथ साइबर ठगी, एकाउंट से निकल गए रुपए

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जबलपुर में एक बार फिर साइबर ठगों ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। यहां पर माता गुजरी कालेज की प्रोफे सर दीप्ति दीक्षित के साथ साइबर ठगी हुई है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया है। पुलिस के अनुसार मल्होत्रा कम्पाउंड सदर में रहने वाली महिला दीप्ति दीक्षित उम्र 49 वर्ष माता गुजरी कालेज मढ़ाताल सिविक सेन्टर में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ है। वे अपनी पति धीरज के साथ फैमली ट्रिप में जगन्नाथ पुरी उड़ीसा गई थी। वे पुरी से कटनी ट्रेन से आई, इसके बाद वे बस में बैठकर कटनी से जबलपुर सुबह लगभग 07 बजे घर सदर आए। इस बीच सफर के दौरान उसका स्वास्थ खराब होने के कारण अपना मोबाइल बिलकुल नही देख पायी। दो-तीन दिन बाद मोबाइल फोन देखा तो 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच उनके खाते से 79783 रुपए निकाल लिए गए। जिसकी शिकायत पहले उन्होने यूनियन बैंक शाखा मढ़ाताल सिविक सेन्टर में की। न्यू कंचनपुर अधारताल में रहने वाली मिताली यादव उम्र 27 वर्ष का एसबीआई बैंक सब्जी मंडी अधारताल में है। वे टेलीग्राम

के माध्यम से एक ट्रेडिंग ग्रुप से जुड़ी रही। जिसमें पैसे इनवेस्ट करने पर प्राफिट मिलता है। शुरुआत में मिताली को इन्वेस्ट करने पर फायदा हुआ। इसके बाद ग्रुप पर विश्वास करके 1 लाख 77 हजार 700 रूपये अलग अलग अकाउण्ट में यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद न प्राफिट मिला न रुपए। हनुमंत नगर अमखेरा निवासी निजामुद्दीन अंसारी बेल्डिंग का काम करता है उसका बचत खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधारताल शाखा में है। उसके दोस्त अजहर निवासी मदार छल्ला ने उससे काफी समय पहले 5 हजार रूपये उधार लिये थे जो फोन पर भेजे थे, उसने पैसे चैक किया और अपना काम करने लगा। इसके बाद शाम को सात बजे से मोबाइल फोन पर ओटीपी आने लगे, ओटीपी चैक करने पर उसका मोबाइल हैक हो गया। रात लगभग 2 बजे उसका मोबाइल चालू हुआ पता चला कि उसके बैंक खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति 26 हजार 621 रूपये मोबाइल हैक करके ट्रांसफर कर लिये हैं। समदडिया कालोनी मानेगांव रांझी में रहने वाली खुशी यादव उम्र 24 वर्ष ने इंस्टाग्राम पर सस्ता बाजार नाम की आईडी पर कपड़ों के विज्ञापन का एड देखा था उक्त विज्ञापन को देखकर उसने दिये गये माध्यम से व्हाटसएप नम्बर पर सम्पर्क कर व्हाटसएप के माध्यम से 349 रूपये में ड्रेस आर्डर कर दी।

अंतिम संस्कार के लिए रुपये नहीं बचे, पत्नी का शव नदी में फेंकने जा रहा था, जबलपुर की घटना

जबलपुर। हम गरीब हैं, बेटे ने होटल में प्लेट धोकर रुपये कमाए और मां के इलाज में लगा दिए। अब चूंकि पत्नी की मौत हो गई है मेरे पास इतने पैसे नहीं कि अंतिम संस्कार करा सकूं। इसलिए शव को नर्मदा में फेंक दूंगा। मछलियों के काम तो आएगी। अंतिम संस्कार के लिए रुपये नहीं होने पर गरीब नवाज कमेटी आगे आई और उसकी मदद की। यह बात जबलपुर के 51 साल के श्याम विश्वकर्मा ने कही।

श्याम की पत्नी आरती विश्वकर्मा 41 साल की मंगलवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। श्याम पत्नी का शव लेकर चुपचाप अस्पताल से निकलने की तैयारी कर रहा था। श्याम के अनुसार तभी एक नर्स की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे रोक लिया। करीब 6 माह पहले जबलपुर से 35 किमी दूर मगरमुंहा गांव में उसकी पत्नी आरती की दुर्घटना में चोटिल हुई थी, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। बताया जाता है कि मौत के बाद रुपये नहीं होने पर वह अंतिम संस्कार को लेकर परेशान था और चुपचाप अस्पताल से निकलकर पत्नी का शव नदी में फेंकने की सोच रहा था।

अंतरधार्मिक विवाह को लेकर जबलपुर कलेक्ट्रेट बना छावनी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आवेदन...

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

अंतरधार्मिक विवाह के एक आवेदन को लेकर मंगलवार को जबलपुर कलेक्ट्रेट में सुबह से शाम तक गहमागहमी रही। शाम को विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से तर्क रखे गए।

प्रस्तुत विवाह आवेदन से जुड़ा था मामला - सुनवाई के बाद विवाह पंजीयन अधिकारी ने मोहम्मद शफीक और उसकी हिंदू प्रेमिका के विवाह आवेदन को निरस्त कर दिया। मामला अधारताल निवासी मोहम्मद शफीक और उसकी हिंदू प्रेमिका के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रस्तुत विवाह आवेदन से जुड़ा था।

तर्क सुनने के लिए समय निर्धारित था-मंगलवार को आवेदन पर आई आपत्तियों और पक्षकारों के तर्क सुनने के लिए समय निर्धारित था। सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और सनातन धर्म से जुड़े अधिवक्ता पहुंच गए थे। शाम करीब पांच बजे मुस्लिम पक्ष के लोग भी विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। हिंदू प्रेमिका की मां की ओर से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई। विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष मोहम्मद शफीक पर हिंदू प्रेमिका के माता-पिता के साथ मारपीट करने, तेजाब से जलाने की धमकी देने सहित अन्य आरोप लगाए। आपत्ति पक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि मोहम्मद शफीक पूर्व में हिंदू प्रेमिका को अपने साथ ले जा चुका है और घर से गहने चोरी किए जाने के संबंध में भी आरोप हैं।

प्रेमिका के माता-पिता की सुरक्षा को लेकर आशंका -

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए हिंदू प्रेमिका के माता-पिता की सुरक्षा को लेकर आशंका है और भविष्य में किसी अप्रिय घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने विवाह आवेदन निरस्त करने की मांग की। मोहम्मद शफीक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आवेदन का बचाव करते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत प्रस्तुत विवाह आवेदन कानूनी प्रविधानों के अनुरूप है। केवल आपत्ति लगाए जाने के आधार पर आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष की ओर से अपने तर्क के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों के निर्णय भी विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद विवाह पंजीयन अधिकारी ने मोहम्मद शफीक और उसकी हिंदू प्रेमिका का विवाह आवेदन निरस्त कर दिया। इस मामले में हिंदू धर्म सेना की ओर से मुकेश रजक और हेमराज उपाध्याय, विश्व हिंदू परिषद से आरती शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

रांझी क्षेत्र में आपसी विवाद पर बदमाशों ने किया वृद्ध पर जानलेवा हमला, घर में की तोड़फ़ोड़

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जबलपुर में रांझी स्थित किशन होटल काली मंदिर के समीप रहने वाले सुरेश कोल पर आपसी विवाद के चलते अनिकेत कोल व उसके साथियों ने चाकुओं से प्राणघातक हमला किया। हमले में वृद्ध के शरीर पर गंभीर चोटें आई है। वहीं हमला होते देख भतीजे ने बीच बचाव किया तो उसपर भी हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी घर में तोडफ़ोड़ करते हुए भाग निकले। रांझी पुलिस ने बताया कि सुरेश कोल उम्र 62 वर्ष निवासी किशन होटल काली मंदिर के पास रांझी ड्रायवरी करते है। उनके साथ पुष्पलता कोल नामक महिला रहती है। बीती रात एक बजे के लगभग सुरेश कोल का पुष्पलता से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसपर पुष्पलता ने अपने बेटे अनिकेत को खबर दे दी। जिसपर अनिकेत कोल अपने साथी साहिल कोल, शिवम कोल एवं रचित कोल के साथ घर के बाहर आया। जिसे मां पुष्पलता के इशारे पर सुरेश कोल के साथ गाली गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया,जिससे सुरेश के पेट में चोट आई, इसके बाद अनिकेत व उसके साथियों ने फिर चाकू से हमला कर सीने, पैर व जांघ में वार किए। सुरेश कोल पर हमला होते देख भतीजे अंशुल ने बीच बचाव किया तो उसपर भी चाकुओं से हमला किया। हमले के बाद आरोपियों ने घर में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग घरों से निकल आए, जिन्हे देख हमलावर धमकी देते हुए भाग निकले। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाकर हमलावरों के खिलाफ धारा 331(6),296, 109(1), 118(1), 324(4), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर तलाश शुरु कर दी है।

एमपी हाईकोर्ट का प्रमोशन में आरक्षण पर अंतरिम फैसला

50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा न लांघें मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से करें निगरानी

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन आरक्षण की 50 प्रतिशत निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इस मामले या सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरबी राय और जरनैल सिंह मामलों में फैसला आने तक प्रमोशन में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का सख्ती से पालन हो। सुनवाई के दौरान भोपाल की वेटरनरी सर्जन डॉ। स्वाति तिवारी सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर बहस हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को लगातार प्रमोशन दिए जा रहे हैं। एक बार प्रमोशन मिलने के बाद संबंधित कर्मचारियों को बाद में पदावनत यानी रिवर्ट करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरबी राय मामले का हवाला देते हुए कहा कि स्पष्ट कानूनी स्थिति होने के बावजूद अब तक प्रभावित कर्मचारियों को रिवर्ट नहीं किया गया है।

इंद्रा साहनी फैसले का हवाला

डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ फैसले में निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, लेकिन आरक्षण की निर्धारित 50 प्रतिशत ऊपरी सीमा का पालन भी जरूरी है। इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि लंबित मामलों में अंतिम निर्णय आने तक प्रमोशन प्रक्रिया में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और अतिरिक्त महाधिवक्ता जान्हवी पंडित ने सरकार का पक्ष रखा।

जटिल नहीं, जादुई है केमिस्ट्री : रसायन विज्ञान को विद्यार्थियों के लिए कैसे बनाएं रोचक और सरल?

अक्सर स्कूली विद्यार्थियों के बीच एक आम धारणा देखने को मिलती है कि रसायन विज्ञान एक बेहद कठिन और उबाऊ विषय है। आवर्त सारणी (Periodic Table) को रटना, रासायनिक समीकरणों (Chemical Equations) को संतुलित करना और जटिल सूत्रों को याद रखना कई बच्चों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं होता। लेकिन क्या वास्तव में रसायन विज्ञान इतना नीरस है? जवाब है– बिलकुल नहीं। रसायन विज्ञान हमारे जीवन का आधार है। सुबह उठकर ब्रश करने के टूथपेस्ट से लेकर रात को खाए जाने वाले भोजन के पचने तक, सब कुछ केमिस्ट्री ही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे किताबों के पन्नों से बाहर निकालकर विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ें। आइए जानते हैं कि इस विषय को सरल और मजेदार कैसे बनाया जा सकता है।

1. प्रयोगशाला को बनाएं 'जादू का कमरा'

रसायन विज्ञान को केवल ब्लैकबोर्ड पर नहीं सिखाया जा सकता। जब विद्यार्थी अपनी आँखों के सामने दो पारदर्शी रसायनों को मिलकर एक नया रंग बनते देखते हैं, तो उनकी जिज्ञासा जाग उठती है। दैनिक जीवन के प्रयोग– सिरका और बेकिंग सोडा मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुब्बारा फुलाना या नींबू के रस से अदृश्य स्याही बनाना–ऐसे छोटे–छोटे प्रयोग विज्ञान के प्रति बच्चों का नजरिया बदल देते हैं।

2. 'विजुअलाइजेशन' और डिजिटल टूल्स का उपयोग

आज का युग डिजिटल है। XD एनिमेशन और सिमुलेशन ऐप्स जैसे PhET Simulations के जरिए परमाणु **(Atoms)**, अणु (Molecules) और उनके बीच बनने वाले बंध (क्ष्ठ्ठस्त्र्ह्य)

को स्क्रीन पर जीवंत रूप में देखा जा सकता है। जब बच्चे पानी के अणु (H w O) की संरचना को सामने बनते देखते हैं, तो उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती।

3. 'स्मार्ट ट्रिक्स' और कहानियों से याद करें आवर्त सारणी

आवर्त सारणी के तत्वों को याद रखने के लिए पारंपरिक रटने की विधि के बजाय मजेदार 'नेमोनिक्स' या कविताओं का सहारा लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, पहले समूह के तत्वों (॥, ख्र्, ह्रु, च, ऋ्ह्ब, ष्ह्य, स्र्ह) को ×ह्लह्वशह्ल;हे ली ना की रब से फरियाद×ह्लह्वशह्ल; जैसी पंक्तियों से हँसते–खेलते याद किया जा सकता है।

4. रसोईघर: घर की सबसे बड़ी केमिस्ट्री लैब

शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों को यह समझाना होगा कि हमारी रसोई ही सबसे पहली प्रयोगशाला है। दूध से दही का बनना (किण्वन)। लोहे के तवे पर जंग लगना (ऑक्सीकरण)। सब्जी में हल्दी का रंग बदलना (प्राकृतिक सूचक)। जब बच्चे इन घटनाओं के पीछे का विज्ञान समझेंगे, तो विषय अपने आप सरल लगने लगेगा।

शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका अहम

रसायन विज्ञान को रटाने के बजाय 'क्यों और कैसे' के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाना चाहिए। परीक्षा में केवल अंक लाने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों को समझने के लिए केमिस्ट्री को अपनाना जरूरी है। रसायन विज्ञान को कठिन से सरल बनाने की चाबी 'करके सीखने' में है। यदि हम शिक्षण पद्धतियों में थोड़ा सा नवाचार, थोड़े से प्रयोग और ढेर सारी उत्सुकता शामिल कर दें, तो यही केमिस्ट्री विद्यार्थियों का सबसे पसंदीदा विषय बन सकती है। जरूरत सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की है।

श्रीमती अर्चना गुप्ता
प्राचार्य
हितकारिणी चिल्ड्रंस एकेडमी
जोंसगंज, जबलपुर

विज्ञान के रोचक प्रयोग

धागे पर नमक के क्रिस्टल

यह प्रयोग कला और विज्ञान का अनूठा संगम है, जिससे सुंदर नमक के क्रिस्टल बनते हैं। यह बच्चों को वाष्पीकरण, क्रिस्टल निर्माण और विभिन्न पदार्थों की संरचना के बारे में सिखाने का एक बेहतरीन तरीका है।

आवश्यक सामग्री

टेबल नमक, पानी, एक कांच का जार, एक धागा, एक पेंसिल।

कैसे करें

सबसे पहले, एक बर्तन में पानी गर्म करें और धीरे–धीरे नमक तब तक डालें जब तक वह घुलना बंद न हो जाए। अपने धागे को पेंसिल से बांधें और पेंसिल को जार के ऊपर सीधा रखें। फिर, धागे को सावधानी से घोल में डालें, ध्यान रहे कि वह जार के किनारों को न छुए। कुछ दिनों में, जैसे–जैसे पानी वाष्पित होता जाएगा, धागे पर नमक के क्रिस्टल बनते जाएंगे।

यह कैसे काम करता है

यह प्रक्रिया वाष्पीकरण पर आधारित है। जैसे–जैसे जार में पानी वाष्पित होता है, घुला हुआ नमक धागे पर ठोस क्रिस्टल के रूप में रह जाता है। नमक के क्रिस्टल का बनना बच्चों को यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि अणु मिलकर ठोस संरचनाएं कैसे बनाते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए बच्चों को धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये छोटे–छोटे क्रिस्टल समय के साथ कैसे बढ़ते हैं।

आधुनिक युग में विज्ञान शिक्षा का रूपांतरण

आधुनिक युग में विज्ञान शिक्षा के स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले विज्ञान की पढ़ाई मुख्य रूप से पुस्तकों और शिक्षक के व्याख्यान तक सीमित रहती थी, लेकिन आज इसमें प्रयोग, गतिविधि, तकनीक और खोज को अधिक महत्व दिया जाता है। विद्यार्थी केवल तथ्यों को याद नहीं करते, बल्कि उन्हें समझकर अपने जीवन से जोड़ते हैं। प्रयोगशालाएँ, मॉडल और वैज्ञानिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तर्कशक्ति तथा समस्या–समाधान की क्षमता विकसित करती हैं। विज्ञान शिक्षा के रूपांतरण में डिजिटल तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्मार्ट कक्षाएँ, कंप्यूटर, इंटरनेट, शैक्षिक वीडियो और डिजिटल प्रयोग विद्यार्थियों को कठिन विषयों को सरलता से समझने में सहायता करते हैं। अब विद्यार्थी किसी भी वैज्ञानिक विषय की जानकारी अलग–अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा ने सीखने को अधिक सरल, रोचक और सुविधाजनक बनाया है। इससे विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं और नए प्रयोगों तथा वैज्ञानिक विचारों को आसानी से समझ

सकते हैं। आज विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच विकसित करना है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, कारण खोजने, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। विज्ञान शिक्षा उन्हें पर्यावरण, स्वास्थ्य, ऊर्जा और तकनीक जैसी वास्तविक समस्याओं को समझने में सहायता करती है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ–साथ आत्मनिर्भर, तार्किक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है।

प्रश्न-उत्तर

1. प्रश्न – आधुनिक विज्ञान शिक्षा में किसे अधिक महत्व दिया जाता है?

उत्तर – आधुनिक विज्ञान शिक्षा में प्रयोग, गतिविधि, तकनीक और खोज को अधिक महत्व दिया जाता है।

2. प्रश्न – विज्ञान शिक्षा में डिजिटल तकनीक की क्या भूमिका है?

उत्तर – डिजिटल तकनीक कठिन विषयों को सरल, रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाती है।

3. प्रश्न – आधुनिक विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर – इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कशक्ति और रचनात्मक सोच विकसित करना है।

4. प्रश्न – प्रयोगशालाएँ विद्यार्थियों के लिए क्यों उपयोगी हैं?

उत्तर – प्रयोगशालाएँ विद्यार्थियों को विज्ञान को प्रयोग करके समझने का अवसर देती हैं।

5. प्रश्न – आधुनिक विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को किस प्रकार तैयार करती है?

उत्तर – यह विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, तार्किक, रचनात्मक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है।

शिवानी तिवारी
शिक्षिका
आदर्श हितकरिणी चिल्ड्रन
गोविंदगंज, जबलपुर

विज्ञान की कक्षा को रोचक कैसे बनाएं

विज्ञान महज एक विषय नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। इस विषय का अध्ययन करने से पाठकों और विद्यार्थियों को अनेक आयामों का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। चाहे गुरुत्वाकर्षण को समझना हो, रसायनों की क्रिया का अध्ययन करना हो या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना हो, इस विषय के अनगिनत लाभ हैं। हालांकि, मुख्य प्रश्न यह है कि विज्ञान को रोचक विषय कैसे बनाया जाए और विद्यार्थियों में कम उम्र से ही जिज्ञासा कैसे पैदा की जाए। अक्सर विद्यार्थी बड़े होने पर इस विषय में रुचि खो देते हैं। इसलिए, उनमें प्राथमिक विद्यालय के समय जैसी जिज्ञासा को जीवित रखना और उन्हें इस विषय से विमुख न होने देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञान में पाठ्यक्रमों और करियर के अवसरों सहित कई रोमांचक विकल्प मौजूद हैं। एचएससी 12वीं विज्ञान के बाद किए जाने वाले पाठ्यक्रमों पर हमारा ब्लॉग पढ़ें, ताकि आपमें इस विषय के प्रति उत्साह और लगाव पैदा हो सके। इसके 5 सबसे प्रभावी तरीके ये हैं–

क्यों का उत्तर देना

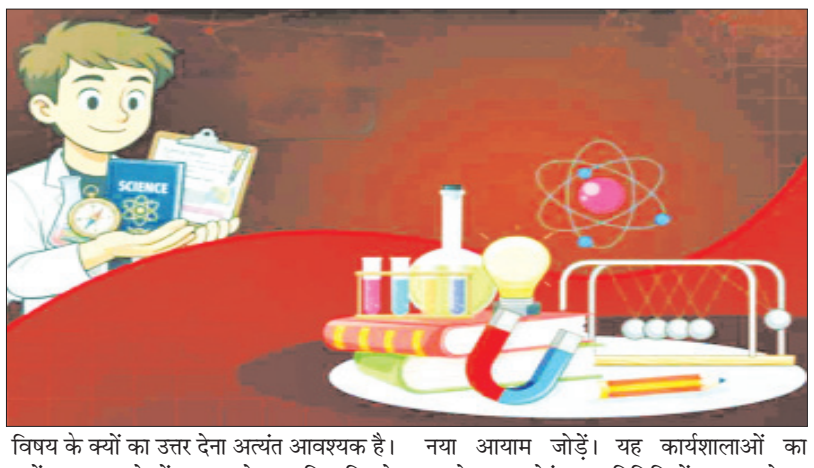

विद्यार्थियों द्वारा पूछा जाने वाला सबसे पहला प्रश्न है क्यों। इस प्रश्न का उत्तर देना बच्चों के मन में जिज्ञासा जगाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए, उनमें जिज्ञासा पैदा करने का सबसे पहला तरीका है इसी क्यों को समझना और उन्हें स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना, जिससे अध्ययन रुचिकर बन जाए।

एक ठोस आधार तैयार करना

अक्सर शिक्षक द्वारा विषय पर सीधे चर्चा शुरू करने से विद्यार्थी विषय को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक एक मजबूत अवधारणात्मक आधार नहीं बनाते हैं। इसलिए, विषय के क्यों का उत्तर देना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि वे विषय क्यों सीख रहे हैं। यह विषय के शीर्षक को अधिक रोचक बनाकर किया जा सकता है।

छात्रों को केवल तथ्यों से ऊबने न दें

विज्ञान विषय को लेकर विद्यार्थियों में एक आम गलत धारणा यह है कि यह केवल तथ्यों पर आधारित है जिन्हें रटा जा सकता है। इससे बच्चों की जिज्ञासा कम हो जाती है, और बाद में उन्हें इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं लगता। हालांकि विज्ञान सिद्ध तथ्यों पर आधारित है, लेकिन शिक्षण विधि में बदलाव करके इसे रोचक बनाया जा सकता है।

सीखने के तरीके को समझना

क्यों को समझने और उसका अध्ययन करने के बाद, अगला चरण है सीखने के तरीके को समझना। विषय को रुचिकर बनाने का एक बेहतरीन तरीका है, भविष्य में इसके उपयोग के बारे में जिज्ञासा जगाना। शिक्षण प्रक्रिया में एक नया आयाम जोड़ें। यह कार्यशालाओं का आयोजन, मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन और छात्रों की सोचने की क्षमता को विकसित करके किया जा सकता है।

सीखने की प्रक्रिया को खुला रखें

विज्ञान सीखते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसे छात्रों के लिए खुला रखना। उन्हें किताबें पढ़कर परिकल्पनाएँ बनाने दें, जिससे उन्हें विषय की गहरी समझ प्राप्त हो सके। विज्ञान का अर्थ है अधिक जानने की ललक पैदा करना। प्राथमिक शिक्षा के दौरान छात्रों को यह विषय रुचिकर लगता है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर पहुँचते–पहुँचते यह रुचि अक्सर कम हो जाती है। इससे 12वीं के बाद यह विषय एक अच्छा करियर विकल्प बन सकता है, जिससे छात्र इंजीनियरिंग और चिकित्सा के लिए अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के साथ–साथ जेईई मेंस, नीट यूजी और एमएचटी सीईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में भाग ले सकें।

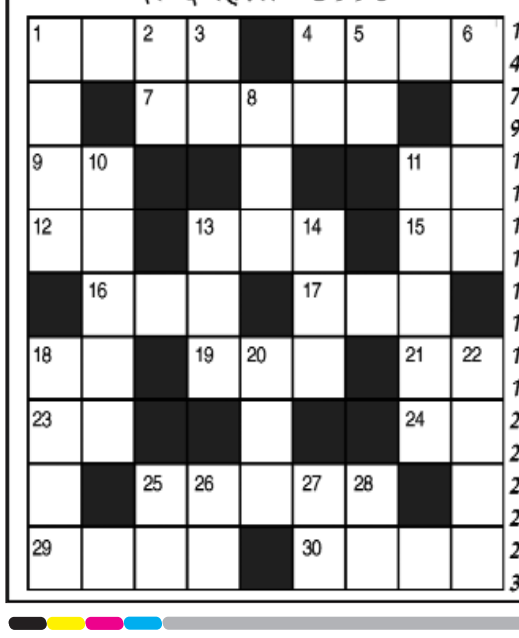

शब्द पहेली - 8970

बाएँ से दाएँ

1. जनमत-4
4. सचेत, सजग-4
7. सहयात्री, संगी-5
9. रुपया, पैसा -2
11. छोटी सवारी गाड़ी-2
12. घ्राणेंद्रिय-2
13. बेकार-3
15. झुका हुआ-2
16. बसंत काल-3
17. टिड्डा-3
18. अन्वेषण, ढूंढना-2
19. जलने की प्रक्रिया-3
21. एक विदेशी शराब-2
23. कला, हुनर-2
24. मैदे की एक प्रकार की रोटी-2
25. आत्मबलिदानी-5
29. करामात-4
30. नामसूची-4

ऊपर से नीचे

1. पूजा, प्रार्थना-4
2. मार्ग, पथ-2
3. यमराज, मृत्युदेवता-2
4. स्वच्छ-2
5. दूल्हा, वरदान-2
6. द्वेष, ईर्ष्या-4
8. तमीज, तहजीब-3
10. सेंधमार-5
11. चुगली करना-5
13. देवर्षि-3
14. रसद, खाद्य सामग्री-3
18. भयानक, डरावना-4
20. अक्षर (उर्दू-3)
22. संजीव कुमार व लीना चंदावरकर की फिल्म-5
25. तेज, सत्य-2
26. ईश्वर, भगवान-2
27. रुदन, क्रंदन-2
28. मोमबत्ती (उर्दू-2)

शब्द पहेली -8969 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

संपादकीय

मौत की इमारतें

दिल्ली देश की राजधानी है अथवा मौत की इमारतों का महानगर है! यह इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में मालवीय नगर के एक 'अवैध', संकरे कथित होटल में अग्निकांड हुआ, जिसमें 22 जिंदगियां भस्म होकर राख बन गईं। कभी राजेन्द्र नगर में बारिश का पानी भर जाता है, उसमें करंट भी प्रवाहित होने लगता है, नतीजतन आधा दर्जन युवा छात्र अचानक लाश बन जाते हैं। वे आईएएस बनने का सपना लिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मौत ने सबकुछ छीन लिया। कभी लक्ष्मीनगर में हादसा हुआ और फिर युवा जिंदगियों पर विराम लग गया। इसी जुलाई में ही रोहिणी में इमारत गिरी, साकेत और करोल बाग में हादसे हुए। मुस्तफाबाद में 11 मौतें इससे पहले हो चुकी थीं। ये हादसे, मौतें नहीं, बल्कि हत्याएं हैं, क्योंकि बचने के बंदोबस्त 'शून्य' थे। अब संभ्रांत कॉलोनी मोतीबाग के पास सत्य निकेतन में भी एक 5-मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस हादसे में 5 मौतों की पुष्टि हुई है। तीन छात्र अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इन तमाम इमारतों में एक तथ्य साझा है कि सभी 'अवैध' थीं। न अग्निशमन विभाग का एनओसी, न नगर निगम का एनओसी, स्वीकृत मंजिलों से अधिक मंजिलों का निर्माण और कई इमारतें तो सालों पुरानी थीं, जिनका रखरखाव भी नहीं किया गया था। सत्य निकेतन वाली इमारत भी 36 साल पुरानी बताई गई है। उस पर विभाग ने सील लगा दी थी, लेकिन फिर न जाने कैसे, वह सील भी खुल गई और यह हत्याकांड हो गया। इस इमारत की तीन मंजिलें 'अवैध' थीं, क्योंकि उसे भूतल और पहली मंजिल बनाने की ही अनुमति दी गई थी, लेकिन भूतल के ऊपर भी चार मंजिलों का निर्माण कर लिया गया। दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व चेयरमैन और फायर ब्रिगेड के पूर्व निदेशक ने चौंका देने वाला खुलासा किया है कि दिल्ली में करीब 75 लाख इमारतें हैं। उनमें से करीब 1.75 लाख इमारतों के नक्शे पास हैं। शेष सभी इमारतें अवैध और अतिक्रमण की हैं। देश की राजधानी में 1731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। उनमें से 1511 को अधिकृत, नियमित करने के मद्देनजर पीएम-उदय योजना के तहत रखा गया है। एक पुख्ता वोट बैंक की तैयारीज्लेकिन यह कितना भयावह यथार्थ है! यदि इन अवैध, अनधिकृत इलाकों में कोई इमारत भरभरा कर गिर पड़ती है, तो कल्पना कीजिए कि नुकसान कितना होगा? सरकार मुआवजा भी नहीं देगी। बहरहाल दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अप्रैल, 2025 के बाद से 241.51 एकड़ जमीन पुन: वापस ली है या प्रक्रिया में है। इसके अलावा, 235 एकड़ से अधिक जमीन पर जो अतिक्रमण, अवैध कब्जे थे, उन्हें मुक्त कराने का अभियान भी तय किया गया है। एक अनुमान है कि 70-75 फीसदी दिल्ली में अवैध या अतिक्रमण वाले कब्जे या निर्माण हैं। झुग्गी-झोपड़ियों पर बुलडोजर चला कर तो गरीबों को बेघर किया जा सकता है, लेकिन राजधानी में जो अतिक्रमणकारी फॉर्म हाउस हैं, उन पर निर्णायक, मिट्टी-मलबा करने वाली कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो दिखावे के लिए कुछ आंशिक तोड़-फोड़ जरूर की गई है। बहरहाल सत्य निकेतन की जो इमारत गिरी है, उसमें डिब्बेनुमा कुछ कमरे बनाए गए थे, जिन्हें 'हॉस्टल' का नाम दिया गया था। एक कमरे में, एक बिस्तर का किराया 15,000-18,000 रुपए माहवार वसूल रहे थे। संकरे रास्ते, संकरी-एकतरफा सीढ़ियां और आपातकालीन बंदोबस्त 'शून्य' थे। ऐसी इमारत के बेसमेंट में, बरसात के मौसम में, भरे पानी की स्थिति में कुछ निर्माण-कार्य किया जा रहा था। ऐसे में नींव का एक पिलर खिसका और पूरी इमारत धड़ाम से धरती पर गिरी। इन कमरों में केरल, हरियाणा, उप्र और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के वे छात्र रहते थे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे।

भारत का ई-बाजार

सुविधा से आगे टिकाऊ अर्थव्यवस्था की नई चुनौती

ललित गर्ग

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं

भारत में खरीदारी की दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, वह केवल बाजार की शैली में परिवर्तन नहीं है, बल्कि उपभोक्ता व्यवहार, रोजगार, तकनीक, छोटे व्यापार और अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना में हो रहे बदलाव का संकेत है। हाल में शोध परामर्श संस्था इन्फिसम की रिपोर्ट ने इस परिवर्तन को एक स्पष्ट आंकड़े में सामने रखा है। उसके अनुसार भारत का ई-बाजार 2024 के लगभग 125 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक करीब 345 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी छह वर्षों में लगभग तीन गुना विस्तार। इसके लिए लगभग 18.4 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। लेकिन इस आंकड़े को केवल बाजार की सफलता के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। असली प्रश्न यह है कि इतनी तेज वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, उपभोक्ता अधिकार, छोटे व्यापार और पर्यावरण के लिए किस तरह का भविष्य बनाएगी। ई-बाजार की अगली कहानी केवल अधिक बिक्री की नहीं, बल्कि अधिक विवेकपूर्ण और अधिक टिकाऊ विकास की होनी चाहिए।

ई-बाजार का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि उसने दुकान को स्थान से निकालकर व्यक्ति की हथेली तक पहुंचा दिया है। पहले ग्राहक बाजार जाता था, अब बाजार ग्राहक के मोबाइल में पहुंच गया है। दुकान खुलने और बंद होने का समय समाप्त हो रहा है। भौगोलिक दूरी का महत्व घट रहा है और सुविधा खरीदारी का सबसे बड़ा आकर्षण बनती जा रही है। इसी कारण ऑनलाइन खरीदारी अब केवल महानगरों की सुविधा नहीं रही। छोटे शहर और कस्बे इसके नए केंद्र बन रहे हैं। हालिया अध्ययन के अनुसार नए प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता आदेशों का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों से आ रहा है। यह परिवर्तन भारत की आर्थिक संरचना के लिए विशेष महत्व रखता है। महानगरों के बाद अब छोटे शहरों का उपभोक्ता बाजार की अगली शक्ति बन रहा है। स्थानीय भाषा में सामग्री, क्षेत्रीय पसंद, छोटे व्यापारियों की डिजिटल उपस्थिति और कम लागत वाली आपूर्ति व्यवस्था आने वाले वर्षों में ई-बाजार के विस्तार को गति दे सकती है। इसलिए भविष्य का ई-बाजार केवल तकनीक का बाजार नहीं होगा, बल्कि भारत की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और स्थानीय आवश्यकताओं को समझने वाला बाजार होगा।

इस बदलाव में नई पीढ़ी की भूमिका निर्णायक है। आज ऑनलाइन खरीदारों में नई पीढ़ी की हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई बताई जा रही है और अनुमान है कि 2030 तक यही वर्ग डिजिटल खर्च का सबसे बड़ा समूह बन सकता है। यह केवल उम्र का परिवर्तन नहीं है, यह उपभोग की मानसिकता का परिवर्तन है। नई पीढ़ी विकल्पों की तुलना करती है, मूल्य की जांच करती है, दूसरे ग्राहकों की राय पढ़ती है और सुविधा को बहुत महत्व देती है। उसके लिए खरीदारी केवल वस्तु प्राप्त करना नहीं, बल्कि समय बचाना भी है। यही मानसिकता त्वरित वाणिज्य को असाधारण गति दे रही है। कुछ वर्ष पहले कुछ मिनटों में सामान पहुंचाने की कल्पना असंभव लगती थी, आज यह महानगरों से निकलकर छोटे शहरों तक पहुंच रही है। अनुमान है कि 2030 तक त्वरित वाणिज्य का बाजार 65 से 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है और अगले पांच वर्षों में ई-बाजार की अतिरिक्त वृद्धि में इसका योगदान 45 से 50 प्रतिशत तक हो सकता है। इसके साथ छोटे स्थानीय भंडार केंद्रों की संख्या 2025 के लगभग 2,525 से बढ़कर 2030 तक करीब 7,500 होने का अनुमान है।

लेकिन यहां एक गंभीर प्रश्न भी खड़ा होता है-क्या हर वस्तु को कुछ मिनट में घर पहुंचाना वास्तव में प्रगति का अंतिम मानक है? यदि उपभोक्ता को पांच मिनट में सामान मिल जाए, लेकिन उस सुविधा के पीछे अत्यधिक पैकेजिंग, अधिक यातायात, अधिक ऊर्जा खपत, अस्थिर रोजगार और लगातार घाटे का व्यापार हो, तो ऐसी गति को कितने समय तक टिकाऊ कहा जा सकता है? इसलिए आने वाले समय में ई-बाजार की सफलता को केवल वितरण की गति से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और आर्थिक संतुलन से भी मापना होगा। प्रौद्योगिकी इस पूरी व्यवस्था को और गहराई से बदलने वाली है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्राहक की पसंद को समझकर उत्पाद सुझाएगी, संवाद आधारित खरीदारी ग्राहक को बातचीत के माध्यम से निर्णय लेने में सहायता देगी और आभासी परीक्षण से वस्त्र, सौंदर्य सामग्री तथा अन्य उत्पादों को खरीदने का अनुभव बदल सकता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यंत्र-अधिगम 2030 तक खुदरा उत्पादकता में 35 से 37 प्रतिशत तक सुधार ला सकते हैं। इससे आगे एक और बड़ा परिवर्तन संभव है। आज ग्राहक स्वयं वस्तु खोजता है, कल कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसके लिए खोज, तुलना और चयन का बड़ा हिस्सा कर सकती है। अर्थात बाजार में सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी केवल वह कंपनी नहीं होगी जिसके पास अधिक उत्पाद हैं, बल्कि वह होगी जो ग्राहक की आवश्यकता को उससे पहले समझ सके। यह सुविधा जहां समय बचाएगी, वहीं उपभोक्ता की स्वतंत्र पसंद, निजता और आंकड़ों की सुरक्षा से जुड़े नए प्रश्न भी पैदा करेगी। ई-बाजार का विस्तार परंपरागत दुकानदार के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऑनलाइन कीमतों की तुलना करने वाला ग्राहक अब दुकान पर भी अधिक जागरूक होकर पहुंचता है। लेकिन इसे केवल ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन संघर्ष के रूप में देखना गलत होगा। भविष्य का सफल व्यापारी संभवत: दोनों का मेल करेगा। स्थानीय दुकानदार डिजिटल माध्यम से आदेश ले सकता है, घर तक सामान पहुंचा सकता है और अपने पुराने ग्राहक संबंधों को तकनीकी सुविधा से जोड़ सकता है। इस प्रकार ई-बाजार परंपरागत बाजार का अंत करने के बजाय उसे नए रूप में ढाल सकता है। दूसरी ओर रोजगार का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ई-बाजार ने वितरण, भंडारण, पैकिंग, तकनीकी सेवाओं और घरेलू आपूर्ति में लाखों अवसर पैदा किए हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता, मेहनताना, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा को लेकर प्रश्न बने हुए हैं। यदि आर्थिक वृद्धि का लाभ केवल कंपनियों और निवेशकों तक सीमित रह जाए और अंतिम पंक्ति में काम करने वाले व्यक्ति को असुरक्षित रोजगार मिले, तो यह विकास अधूरा माना जाएगा।

पर्यावरण भी इसी बहस का महत्वपूर्ण पक्ष है। हर वस्तु की अलग पैकिंग, बार-बार होने वाली छोटी आपूर्ति और अत्यंत तेज वितरण से ऊर्जा उपयोग तथा अपशिष्ट बढ़ सकता है। इसलिए भविष्य का ई-बाजार पुनर्चक्रण योग्य पैकेजिंग, विद्युत वाहनों, सामूहिक वितरण और कम-अपशिष्ट आपूर्ति व्यवस्था की ओर बढ़े, तभी उसकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता सिद्ध होगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि भविष्य की खरीदारी केवल कंपनियां नहीं, बल्कि सामग्री निर्माता और सामाजिक माध्यमों से प्रभावित होगी। गूगल और डेलॉइट के 2026 के अध्ययन के अनुसार 2030 तक नई पीढ़ी ऑनलाइन खर्च का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित कर सकती है और सामग्री निर्माता कुल खुदरा खर्च के लगभग 30 प्रतिशत को प्रभावित कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि विज्ञापन और खरीदारी के बीच की पुरानी दूरी तेजी से मिटेगी। विश्वास, अनुभव और सामाजिक प्रभाव वस्तु की कीमत जितने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इसलिए 2030 का ई-बाजार आज के ई-बाजार से बिल्कुल अलग होगा। वह केवल इंटरनेट पर बनी दुकान नहीं होगा, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्थानीय भाषाओं, डिजिटल भुगतान, त्वरित वितरण, सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत सुझावों से निर्मित एक विशाल आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र होगा। अनुमान है कि दशक के अंत तक ई-बाजार भारत के कुल खुदरा खर्च का 10 से 12 प्रतिशत और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगभग 2.5 प्रतिशत योगदान कर सकता है तथा 42 से 44 करोड़ ऑनलाइन खरीदारों तक पहुंच सकता है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाजार का आकार जितना बड़ा होगा, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। ई-बाजार की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह कितनी तेजी से बढ़ता है, बल्कि यह है कि वह कितने लोगों को साथ लेकर बढ़ता है। यदि तकनीक सुविधा दे, छोटे व्यापारी अवसर पाएं, उपभोक्ता सुरक्षित रहे, कामगार को सम्मानजनक रोजगार मिले, पर्यावरण पर बोझ घटे और कंपनियां टिकाऊ मुनाफे के साथ आगे बढ़ें, तभी यह विस्तार वास्तविक आर्थिक प्रगति कहलाएगा। भारत के ई-बाजार के सामने इसलिए एक बड़ा अवसर और एक बड़ी चेतावनी दोनों हैं। 345 अरब डॉलर का लक्ष्य आकर्षक है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है उस बाजार की गुणवत्ता। हमें ऐसा ई-बाजार चाहिए जो केवल खरीदारी को तेज न बनाए, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी, अधिक विश्वसनीय, अधिक मानवीय और अधिक टिकाऊ बनाए। आने वाले वर्षों में जीत उसी की होगी जो ग्राहक को केवल वस्तु नहीं, विश्वास, सुविधा और मूल्य-तीनों एक साथ दे सके। यही ई-बाजार की अगली और सबसे महत्वपूर्ण क्रांति होगी।

वीडियो गेम में चलते युद्ध का प्रवेश: मनोवैज्ञानिक युद्ध से कैसे बदल रहा राजनीतिक प्रचार?

संजय वर्मा

वीडियो गेम कोई समस्या नहीं है। चिंता तब होती है, जब सरकारें युद्ध, राजनीति और मनुष्यों के विस्थापन को वीडियो गेम की भाषा में प्रस्तुत करने लगती हैं।

वीडियो गेम की दुनिया में हार के बाद एक विकल्प हमेशा बचा रहता है-'प्ले अगेन'। खिलाड़ी फिर से शुरुआत कर सकता है। लेकिन, हकीकत में ऐसा कोई बटन नहीं होता। युद्ध में डूबी नौका, सीमा से खदेड़ा गया परिवार या बारूदी सुरंग की चपेट में आए व्यक्ति के लिए कोई 'रीस्टार्ट' नहीं होता। चिंता तब पैदा होती है, जब सरकारें राजनीति, युद्ध और मनुष्यों के विस्थापन को वीडियो गेम की भाषा में प्रस्तुत करने लगती हैं। सितंबर की शुरुआत में लगभग एकसाथ सामने आई अमेरिका और ईरान की दो घटनाएं इसी बदलती दुनिया की ओर संकेत करती हैं।

अमेरिका के व्हाइट हाउस ने अपनी नीतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए रेट्रो शैली के ऑनलाइन गेमों का एक पिटारा पेश किया। इनमें 'रियो रन' में खिलाड़ी अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर प्रवासियों जैसे दिखने वाले पात्रों को रोकता व 'निर्वासित' करता है। दूसरे गेम 'बिल्ड द वॉल' में टेट्रिस की तरह दीवार बनाकर सीमा को कथित घुसपैठ से बचाना है। लगभग इसी समय ईरान ने भी वीडियो गेम की सांस्कृतिक भाषा को भू-राजनीतिक हथियार बना दिया। सिएरा लियोन स्थित ईरानी दूतावास ने 35 सेकंड का एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को लोकप्रिय कंप्यूटर गेम 'माइंसवीपर' की स्क्रीन में बदल दिया गया। संदेश था-'हबीबी (अंकल सैम), ईरान आओ।' इस वीडियो के सामने आने के दौरान ईरान के होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और होर्मुज में सुरक्षित नौवहन को लेकर अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ रहा था।

इन दोनों घटनाओं को केवल इंटरनेट पर की गई हल्की-फुल्की टिप्पणी या डिजिटल प्रचार मानना भूल होगी। इनके भीतर 21वीं सदी के राजनीतिक संचार का नया व्याकरण छिपा है-सत्ता का गेमिफिकेशन। अब तक गेमिफिकेशन का इस्तेमाल शिक्षा, कारोबार, फिटनेस और मार्केटिंग में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए होता रहा है। पर, जब यही तकनीक राजनीति में प्रवेश करती है, तो उसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं रह जाता है। इसकी प्रक्रिया किसी जटिल राजनीतिक मुद्दे को ऐसी कथा में बदल सकती है, जिसमें एक तरफ 'हम', दूसरी तरफ 'वे'; एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी तरफ शत्रु; एक तरफ विजय, दूसरी तरफ पराजय का भाव रहता है।

इन उदाहरणों को देखें, तो वीडियो गेम आधुनिक मनोवैज्ञानिक युद्ध के अत्यंत प्रभावी माध्यम बनते दिखाई देते हैं। मीडिया दार्शनिक मार्शल मैकलुहान की प्रसिद्ध अवधारणा थी कि माध्यम खुद-ब-खुद संदेश को बदल देता है। वीडियो गेम के दौर में इसे एक कदम आगे बढ़ाकर समझने की जरूरत है। अब माध्यम केवल संदेश नहीं बदलता, वह दर्शक की भूमिका भी बदल देता है। इसलिए, राजनीतिक गेमिंग की मनोवैज्ञानिक शक्ति कहीं अधिक हो सकती है। यह प्रवृत्ति खास तौर पर उस पीढ़ी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसकी राजनीतिक सूचनाओं की खपत तेजी से छोटे वीडियो, मीम, रील और इंटरैक्टिव डिजिटल सामग्री की ओर बढ़ी है।

इसके साथ एक नैतिक संकट भी जन्म लेता है कि क्या हर चीज को खेल बनाया जा सकता है? बेशक, खेल वास्तविकता को सरल करता है, लेकिन लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय राजनीति इतनी सरल नहीं। हालांकि, यह भी समझना होगा कि वीडियो गेम्स अपने आप में समस्या नहीं हैं। वे कला, शिक्षा और इतिहास को समझने के प्रभावशाली माध्यम भी हो सकते हैं। लेकिन, समस्या तब शुरू होती है, जब सरकारें उनकी आकर्षक और सहभागी प्रकृति का इस्तेमाल जटिल मानवीय मुद्दों को एकतरफा राजनीतिक कथानक में बदलने के लिए करती हैं। अमेरिका और ईरान के ये प्रयोग भविष्य की ही एक झलक हैं। आने वाले समय में चुनाव प्रचार, सैन्य भर्ती, कूटनीतिक संघर्ष, राष्ट्रवाद और वैचारिक प्रचार में इंटरैक्टिव गेम, एआई अवतार और वर्चुअल दुनिया का इस्तेमाल बढ़ सकता है। संभव है कि भविष्य का राजनीतिक प्रचार हमें केवल यह न बताए कि किसे मित्र और शत्रु मानना है; वह हमें स्वयं उस शत्रु के विरुद्ध डिजिटल कार्रवाई करने को कहे। तब सबसे जरूरी कौशल केवल मीडिया साक्षरता नहीं, बल्कि गेम साक्षरता और एल्गोरिदमिक साक्षरता भी होगी।

नागरिकों को समझना होगा कि खेल के नियम किसने बनाए, जीत की परिभाषा किसने तय की, किस पात्र को नायक और किसे खतरा बनाया गया तथा कौन-सी वास्तविकता जानबूझकर स्क्रीन से बाहर छोड़ दी गई है। माइंसवीपर में खिलाड़ी का उद्देश्य छिपी हुई माइंस पहचानना होता है। आज के डिजिटल नागरिक के सामने भी यही चुनौती है कि वह राजनीतिक मनोरंजन की चमकदार स्क्रीन के नीचे छिपे प्रचार, पूर्वाग्रह और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की 'माइंस' को पहचाने। वीडियो गेम में नई बाजी शुरू की जा सकती है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता।

हम आखिर कर क्या रहे हैं?

संदीप तिवारी एडवोकेट

पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व शासकीय अधिवक्ता, शहडोल

हम देश में निष्पक्ष परीक्षाएँ नहीं करवा पाए, पेपर लीक नहीं रोक पाए, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाए, बेरोज़गारी नहीं रोक पाए, महँगाई से जनता को राहत नहीं दे पाए और अपने युवाओं को बेहतर भविष्य नहीं दे पाए। हम खनिज संपदा और प्रकृति के अंधाधुंध दोहन को नहीं रोक पाए, जंगल कटते रहे, नदियाँ प्रदूषित होती रहीं, जमीन और जल संकट बढ़ता रहा-लेकिन विकास के नाम पर भाषण और विज्ञापन लगातार बढ़ते रहे।

हम सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और छात्रावासों को पर्याप्त सुविधाएँ नहीं दे पाए, लेकिन सत्ता के कार्यालयों और प्रचार तंत्र पर खर्च करने में कोई कमी नहीं रही।हम राम मंदिर के पवित्र चंदे में लगे कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का सच सामने नहीं ला पाए, लेकिन धर्म के नाम पर समाज को बाँटने में पूरी ताकत लगा दी।

हम किसानों की समस्याएँ हल नहीं कर पाए, मजदूरों को सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पाए, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए-लेकिन हिंदू-मुसलमान, दलित-सवर्ण और जाति-धर्म की बहस के लिए हमारे पास हमेशा समय है।

आखिर हमारा विज़न क्या है? एक ऐसा भारत जहाँ शिक्षा मजबूत हो, रोजगार मिले, अस्पताल अच्छे हों, जंगल और खनिज संपदा सुरक्षित रहें, कानून सबके लिए समान हो-या ऐसा भारत जहाँ जनता आपस में लड़ती रहे और सत्ता अपनी कुर्सी बचाती रहे? अंग्रेजों का नारा था-फूट डालो और राज करो। आज नारा है झूठ बोलो, रील बनाओ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनो, जनता को बाँटो और राज करो।

युवा नौकरी माँगे तो भाषण, छात्र निष्पक्ष परीक्षा माँगे तो डंडे, गरीब न्याय माँगे तो प्रक्रिया, किसान राहत माँगे तो आश्वासन और जनता सवाल पूछे तो उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए-क्या यही लोकतंत्र की सफलता है?

देश विज्ञापनों से नहीं चलता, देश विश्वास से चलता है; देश नारों से नहीं चलता, देश शिक्षा, रोजगार, न्याय, स्वास्थ्य, सुरक्षा और ईमानदार शासन से चलता है।

हमें मंदिर भी चाहिए, मस्जिद भी सुरक्षित चाहिए; हमें आस्था भी चाहिए और पारदर्शिता भी; हमें राष्ट्रवाद भी चाहिए, लेकिन उसके साथ असहमति और सवाल पूछने का अधिकार भी चाहिए।

हमने आपको सत्ता इसलिए नहीं दी थी कि आप हमें जाति और धर्म के नाम पर बाँटें; हमने आपको इसलिए चुना था कि आप देश की संपदा बचाएँ, युवाओं का भविष्य बनाएँ और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर दें।

सवाल किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं-सवाल उस पूरी व्यवस्था का है, जिसमें जनता के वास्तविक सवाल पीछे छूट जाते हैं और सत्ता का प्रचार सबसे आगे निकल जाता है।

लोकतंत्र में अंतिम मालिक कोई नेता नहीं, जनता होती है। इसलिए हम सवाल पूछेंगे, बार-बार पूछेंगे-क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य, अपनी प्रकृति और अपने देश की संपदा बचाने के लिए अब चुप रहना संभव नहीं।

आखिर युवाओं के बीच क्यों नहीं चमक पा रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन?

कमलेश पांडे

भाजपा के राजनीतिक गलियारों में एक सवाल सबको बेचैन किए हुए है कि आखिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन युवाओं के बीच क्यों नहीं चमक पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव, आप नेता अरविंद केजरीवाल, जनसुराज नेता प्रशांत किशोर आदि जैसे राजनीतिक क्षत्रपों को सियासी रूप से निपटाने के लिए नितिन नवीन के रूप में जो राजनीतिक तुरूप का पत्ता चला है, वह अब मनहूसियत की ओर अग्रसर है! कहीं विपक्ष के इशारे पर थिरक रहा जेन-जी भारी पड़ रहा है तो कहीं सवर्ण संगठनों का जनप्रदर्शन भाजपा नेतृत्व की रीति-नीति पर सवालों के गोले बरसा रहा है। वहीं कांग्रेस व उसके समर्थक दल जिस तरह से अपने अपने मुद्दों पर भाजपा को घेर रहे हैं, उससे पार्टी के कट्टर समर्थकों में भी ऊहापोह मची हुई है! पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन उनकी उपलब्धि जरूर है, लेकिन सवाल तो यहां तक उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पार्टी की कीमत पर उन्हें एक सीमा के बाद युवाओं के बीच चमकने नहीं देना चाहते और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की तरह सिर्फ अपना-अपना अनुगामी बनाए रखना चाहते हैं? प्रवासीनेटवर्क जुड़ें

चूंकि नितिन नवीन के ऊपर पीएम मोदी का ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए उनपर एक सीमा के बाद बड़े नेता विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं और अफवाह उड़वा रहे हैं कि नितिन नवीन में नैसर्गिक नेतृत्व क्षमता की कमी है? इससे मोदी-भागवत दोनों परेशान हैं। राजनीतिक विश्लेषक की मानें तो यह सवाल असल में नितिन नवीन की व्यक्तिगत क्षमता से यादा भाजपा के सत्ता-संगठन मॉडल का सवाल है? अभी उपलब्ध घटनाक्रम को देखकर सीधे यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह उन्हें चमकने नहीं देना चाहते। लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भाजपा में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की पर्याप्त जगह मिलती है?

देखा जाए तो अगस्त 2026 में नितिन नवीन ने स्वयं Gen Z outreach की रणनीति पर बड़ी बैठक की, जिसमें करीब 45 नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पार्टी ने युवाओं के मुद्दों और उनसे संवाद की रणनीति पर जोर दिया है, हालांकि सर जमीन पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें युवा कम दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा, मेरे आकलन में तीन संभावनाएँ हैं-

पहली, यह नियंत्रित नेतृत्व की रणनीति हो सकती है- भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीतिक ब्रांड-शक्ति इतनी बड़ी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वतंत्र जन-नेता के रूप में उभरना आसान नहीं है। पार्टी अध्यक्ष का प्राथमिक काम संगठन, चुनाव और रणनीति का संचालन रहता है; लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का समानांतर राष्ट्रीय चेहरा बनना उसका घोषित उद्देश्य नहीं होता। इसलिए नितिन नवीन की दृश्यता कम होना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है।

दूसरी, नितिन नवीन अभी राष्ट्रीय नेता बनने की प्रक्रिया में हैं- वे भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी नई राष्ट्रीय टीम में अनुभव तथा युवा ऊर्जा को मिलाने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और राष्ट्रीय जननेता बनना दो अलग चीजें हैं। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय जननेता बनने के लिए चाहिए- अपनी विशिष्ट राजनीतिक भाषा, युवाओं के बीच स्वत: आकर्षण, लगातार देशव्यापी उपस्थिति, कठिन मुद्दों पर स्वतंत्र विचार, संगठन से बाहर भी व्यक्तिगत जनाधार, मीडिया और सोशल मीडिया में अपनी पहचान, लेकिन इनमें से अधिकांश का मूल्यांकन अभी करना जल्दी होगा।

तीसरी, सबसे दिलचस्प संभावना- नितिन नवीन की क्षमता है, लेकिन उनकी राजनीतिक ब्रांडिंग अभी विकसित नहीं हुई है- यही वह जगह है जहाँ मैं आपकी पिछली बात से सहमत हूँ कि युवाओं को जोड़ना केवल कार्यक्रमों से नहीं होगा। पार्टी अभी bike yatras, hackathons, marathons, campus activities और social-media outreach जैसी योजनाओं पर विचार कर रही है। लेकिन युवा किसी नेता से केवल यह नहीं सुनना चाहता कि मोदी सरकार ने यह किया, बल्कि अब वह पूछता है- आप स्वयं मेरे लिए क्या सोचते हैं? यहीं नितिन नवीन को अपनी अलग पहचान बनानी होगी। असली परीक्षा यही है! ऐसे में अगर नितिन नवीन हर भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों के प्रवक्ता बने रहेंगे, तो वे संगठन के सफल अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन युवा जननेता बनने में कठिनाई होगी। लेकिन यदि वे कहें-मोदी जी ने भारत को 2047 का लक्ष्य दिया है; अब मेरी पीढ़ी तय करेगी कि उस भारत की शिक्षा, रोजगार, एआई उद्यमिता और राजनीति कैसी होगी। तो एक अलग राजनीतिक आवाज पैदा होगी।

मेरे पास ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि मोदी या शाह नितिन नवीन को युवाओं के बीच उभरने से रोक रहे हैं। उलटे, उपलब्ध रिपोर्टों में मोदी और शाह की ओर से युवाओं को केंद्र में रखने की बात तथा नितिन नवीन के नेतृत्व में Gen Z outreach को आगे बढ़ाने की तस्वीर मिलती है। लेकिन भाजपा की राजनीतिक संस्कृति में एक संस्थागत सीमा जरूर है, वह यह कि - मोदी = सर्वोच राष्ट्रीय राजनीतिक ब्रांड। शाह = संगठन/रणनीति का शक्तिशाली केंद्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष = संगठन का चेहरा और समन्वयक। नितिन नवीन को इस ढाँचे के भीतर रहते हुए अपनी जगह बनानी होगी।

और अगर प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता की बात करें? तो अभी फैसला देना जल्दबाजी होगा, बल्कि मैं नितिन नवीन के लिए अगले 12-18 महीने को नेतृत्व की अग्निपरीक्षा मानूंगा। तब देखना होगा कि क्या वे युवाओं के बीच बिना प्रधानमंत्री के नाम के भी भीड़ आकर्षित कर सकते हैं? बेरोजगारी, परीक्षा, शिक्षा और ‹ढ्ढ जैसे असुविधाजनक सवालों पर अपनी भाषा विकसित करते हैं? भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ नए युवाओं को भी नेतृत्व में ऊपर लाते हैं? सोशल मीडिया पर केवल पार्टी का संदेश दोहराने के बजाय अपना राजनीतिक विचार रखते हैं? किसी संकट में स्वयं आगे आकर समाधान प्रस्तुत करते हैं? रायों में जाकर नितिन नवीन मॉडल जैसी कोई संगठनात्मक पहचान बनाते हैं? अगर इन छह सवालों का जवाब अगले डेढ़ साल में हाँ होता है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि उनमें प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता नहीं है।वहीं, नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ा खतरा मोदी-शाह से कम और सिर्फ अध्यक्ष रह जाने का यादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वे सफल हो सकते हैं-बैठकें करें, संगठन विस्तार करें, चुनाव जिताएँ, पदाधिकारी नियुक्त करें। उनकी नई राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और युवा नेताओं का मिश्रण भी इसी संगठनात्मक भूमिका की ओर संकेत करता है। लेकिन इतिहास में कुछ अध्यक्ष संगठन के पदाधिकारी बनकर रह जाते हैं और कुछ अपने दौर के राजनीतिक चेहरे बन जाते हैं। लिहाजा, नितिन नवीन को दूसरा रास्ता चुनना होगा। और इसके लिए शायद उन्हें मोदी-शाह से टकराने की जरूरत नहीं है; यह उनका स्वभाव भी नहीं है। इसलिए उन्हें मोदी-शाह की छाया के भीतर अपनी राजनीतिक धूप पैदा करनी होगी। यही उनकी वास्तविक नेतृत्व-परीक्षा है।

ईरान का अंडरवाटर ड्रोन पकड़ने का दावा, अमेरिका ने बढ़ाया प्रतिबंधों का दबाव

तेहरान

पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव के बीच मंगलवार को तनाव और बढ़ गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की नौसेना ने दावा किया कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के पास अमेरिकी नौसेना के एक मानवरहित अंडरवाटर ड्रोन को पकड़ लिया है।

वहीं, अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए उसकी विमानन व्यवस्था से जुड़े 36 ठिकानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी कार्रवाई को तेहरान को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक तंत्र से और अलग-थलग करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, आईआरजीसी नौसेना ने कहा कि उसने एक अत्याधुनिक और मानवरहित अमेरिकी अंडरवाटर ड्रोन को एक जटिल

खुफिया एवं अभियान के दौरान कब्जे में लिया। ईरान का दावा है कि यह उपकरण समुद्र के भीतर खुफिया अभियान चलाने में सक्षम है और इसे 2025 में अमेरिकी सैन्य बेड़े में शामिल किया गया था। ईरानी मीडिया ने इसे 'युद्ध की ट्राफी' के तौर पर पेश किया है।

रिपोर्टों के मुताबिक, यह ड्रोन अमेरिकी रक्षा तकनीक कंपनी एंड्यूरिल का डाइव-एलडी मानवरहित अंडरवाटर वाहन है। कंपनी ने अप्रैल 2025 में अमेरिकी नौसेना की यूनिट को पहला डाइव-एलडी सौंपा था। हालांकि, ईरान के ड्रोन पकड़ने के दावे की अमेरिकी सरकार या सेना की ओर से तत्काल पुष्टि नहीं हुई है।

ईरान के इस दावे के बीच अमेरिका ने मंगलवार को उसके विमानन क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए। एपी के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान की विमानन व्यवस्था को समर्थन देने वाले 36 संस्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाया। इनमें ईरानी एयरलाइंस के साथ विदेशी कंपनियां और ऐसे कारोबारी नेटवर्क भी शामिल हैं, जिन पर ईरान को विमान, कलपुर्जे और तकनीक हासिल करने में मदद करने का आरोप है। अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक, कार्रवाई का निशाना ईरान की सभी बची हुई एयरलाइंस के साथ ऐसे बिचौलिये और कंपनियां भी हैं, जो अमेरिकी मूल के विमानों और संवेदनशील तकनीक की खरीद में तेहरान की मदद करते हैं। मछली पकड़ने वाली कंपनियों या सामान्य विमानन कारोबार के बजाय इस बार कार्रवाई का मुख्य जोर ईरान के विमानन क्षेत्र की उन कड़ियों पर है, जिन्हें अमेरिका हथियार, कर्मियों और अन्य प्रतिबंधित सामान की आवाजाही से जोड़ता है। यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के 'आपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' का हिस्सा है। अमेरिकी ट्रेजरी ने यह अभियान अगस्त में शुरू किया था। इसका घोषित उद्देश्य ईरान की बची हुई आर्थिक और वित्तीय कड़ियों को काटना है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्काट बेसेंट ने कहा कि ईरान की एयरलाइंस को आर्थिक मदद या कारोबारी सहयोग देने वालों को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था से अलग किए जाने का जोखिम उठाना होगा।

यह 1945 का समय नहीं है, एनएससी में सुधारों को लेकर बोले महासभा अध्यक्ष रहमान

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने कहा कि वह सुरक्षा परिषद में अर्थपूर्ण सुधार के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास करेंगे। मंगलवार (स्थानीय समय) को महासभा के अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा, अभी ऐसी स्थिति है जहां भरोसे की कमी है और संगठन को भविष्य के लिए खुद को तैयार करने के लिए और गहरे सुधार करने होंगे। महासभा के अध्यक्ष के तौर पर सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा, मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। वह इंटर-गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के लिए फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति करेंगे। यह 1945 का समय नहीं है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का जिक्र किया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को ध्यान में रखकर की गई थी, एक ऐसा ढांचा जिसमें यह संस्था आज भी फंसी हुई है। उन्होंने कहा, यह 21वीं सदी है। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जनता की नजर में मुख्य संगठन का भरोसा फिर से हासिल करने के लिए सुधार अर्थपूर्ण होने चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री रहमान को जून में अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने अपने देश के यूएन मिशन में काम किया है, न्यूयार्क में अंकटाड के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया है, और सेक्रेटरी-जनरल के एग्जीक्यूटिव आफिस में आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंधी मामलों की जिम्मेदारी संभाली है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ फिर भड़की हिंसा, अलग-अलग घटनाओं में दो हिंदुओं की मौत

ढाका

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच अलग-अलग घटनाओं में एक महिला समेत दो हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जिससे देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हाल की घटनाओं में से एक में 45 वर्षीय हिंदू सुनार अलिफ चंद्र दत्ता की हत्या कर दी गई। सोमवार रात जब वह नौगांव जिले के महादेवपुर उपजिला में अपनी दुकान से घर लौट रहे थे तो अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उन पर हमला किया। पुलिस और स्थानीय लोगों का हवाला देते हुए बांग्लादेश के अखबार डेली सन ने बताया कि दत्ता रात करीब 8:30 बजे महादेवपुर बाजार में अपनी ज्वैलरी की दुकान से निकले थे और घर जा रहे थे, तभी यह घटना हुई। रात करीब 9 बजे जब वह दुललपारा में अपने घर के पास पहुंचे तो हमलावरों के एक समूह ने उन्हें रोका और धारदार हथियार से उन पर हमला किया। खबरों के मुताबिक, हमलावरों ने उनसे सोना और 7 लाख बांग्लादेशी टका नकद लूट लिया और फिर वहां से भाग गए। बाद में परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने घायल दत्ता को बचाया और राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की पुष्टि करते हुए, महादेवपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी उमर फारूक ने कहा, हम अभी तक यह पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि यह केवल लूटपाट थी या घटना के पीछे कोई अन्य दुश्मनी या मकसद था। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई चल रही है। एक अन्य घटना में कॉक्स बाजार जिले के महेशखली उपजिला में 45 वर्षीय हिंदू महिला रानी सुशील की उनके घर के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार शाम करीब 7:30 बजे होनोक यूनियन में हुई, जब एक अज्ञात घुसपैठिए ने चोरी करने की कोशिश करते हुए उन पर हमला किया। पुलिस और के अनुसार, रानी घर पर खाना बना रही थीं तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसने की कोशिश की। उसे देखते ही उन्होंने शोर मचाया। बांग्लादेशी बंगाली दैनिक प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, घुसपैठिए ने कथित तौर पर उनका चेहरा पकड़ लिया और वहां से भागने से पहले कई बार चाकू मारा। घायल रानी को चकारिया उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले गए, जहां कुछ घंटों बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महेशखली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज अब्दुस सुल्तान ने कहा, शुरुआती जानकारी के मुताबिक, एक अनजान व्यक्ति चोरी के इरादे से एक महिला के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर महिला चिल्लाई, चोर, चोर! इसके बाद उस व्यक्ति ने महिला पर चाकू से हमला किया और भाग गया।

लद्दाख में पर्यटन का नया रिकॉर्ड : 8 महीनों में पहुंचे 4.05 लाख पर्यटक, 2025 का आंकड़ा पार

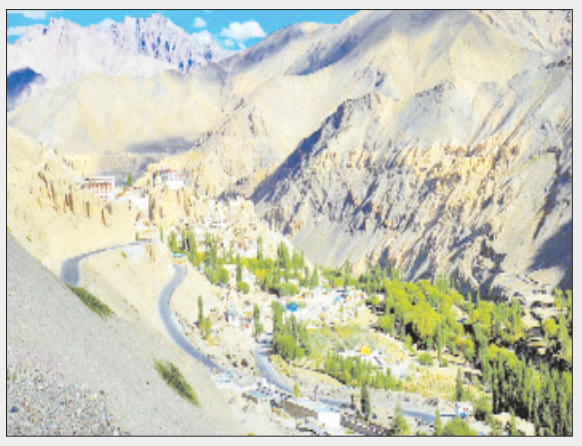

श्रीनगर, वार्ता)। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया गया है। वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों (जनवरी से अगस्त) में ही 4.05 लाख से अधिक पर्यटक लद्दाख पहुंचे हैं। इन आठ महीनों के आंकड़ों ने वर्ष 2025 के पूरे साल के कुल पर्यटन आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साझा किए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी और अगस्त 2026 के बीच 4.05 लाख पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान यह संख्या 2.69 लाख थी। यह वार्षिक आधार पर यह 50.37 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2025 में कुल पर्यटक आगमन 3.35 लाख ही था। क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष जनवरी से अगस्त के बीच लद्दाख में 33,346 विदेशी पर्यटक आए, जबकि 2025 की समान अवधि में यह संख्या 25,082 थी। केवल अगस्त महीने में 2026 में 74,753 पर्यटकों ने लद्दाख का दौरा किया, जो पिछले साल के अगस्त महीने (45,201 पर्यटक) की तुलना में 65.38 प्रतिशत अधिक है।

उपराज्यपाल सक्सेना ने इस वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण, बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र सरकार के निरंतर ध्यान और लद्दाख की पर्यटन-अनुकूल नीति रूपरेखा को दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस क्षेत्र में टिकाऊ, जिम्मेदार और पूरे वर्ष चलने वाली पर्यटन अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ऑफ-सीजन उत्सवों और आयोजनों को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं, कारीगरों और होमस्टे संचालकों के लिए आजीविका के सतत अवसर पैदा किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटकों को शांत और किफायती अनुभव मिल सके।

आईआरजीसी ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस को बनाया निशाना

मास्को, (स्पुतनिक/वार्ता)। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा कि उसने ईरानी तेल टैंकरों पर हुए हमलों के जवाब में जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरानी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने बुधवार को बताया कि जवाबी हमले के दौरान उन्होंने उन इलाकों को निशाना बनाया जहां एफ-35, एफ-16 और एफ-15 लड़ाकू विमान तैनात हैं और उनकी मरम्मत होती है। ईरानी प्रसारक प्रेस टीवी ने बुधवार को बताया कि ईरान ने अल-अज़राक एयर बेस पर हमला किया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने अमेरिकी नौसेना के दो विध्वंसकों पर भी मिसाइल हमले किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार विध्वंसक क्रूज़ मिसाइलों और एजिस प्रणाली युक्त थे। मंगलवार रात, अमेरिकी मध्य कमान ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के पांच टैंकरों को नष्ट कर दिया है।

ऐसे कृत्य स्वीकार नहीं...हूतियों ने सऊदी पर बम बरसाया, भारत को जबरदस्त गुस्सा आया

नई दिल्ली

भारत ने बुधवार को सऊदी अरब में एनर्जी सुविधाओं पर यमन के हूथी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। भारत ने कहा कि ऐसे हमलों से क्षेत्रीय सुरक्षा कमज़ोर होती है और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में नेविगेशन की आज़ादी को खतरा पैदा होता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ये टिप्पणियां भारतीय पक्ष की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया थीं। इससे पहले मंगलवार को हूतियों ने कहा था कि उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन के तहत दक्षिणी सऊदी अरब में तेल की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है। सऊदी अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों के कारण कई तेल प्रतिष्ठानों और यूटिलिटी साइटों पर आग लग गई और 73 लोग घायल हो गए। सऊदी अरब में हूती हमलों का ज़िक्र करते हुए जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र पर हुए हमलों, खासकर आम नागरिकों और आर्थिक सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर करते हैं और बाब-अल-मंदेब में नेविगेशन की आज़ादी के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। दक्षिणी सऊदी अरब में ऊर्जा से जुड़े अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिनमें जिज़ान रिफाइनरी भी शामिल है, जो रोज़ाना 4,00,000 बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती है। ईरान द्वारा होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने के बाद, सऊदी अरब के ऊर्जा निर्यात के लिए बाब-अल-मंदेब का महत्व बढ़ गया है। भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद बढ़ाने के बावजूद, सऊदी अरब देश के शीर्ष तीन ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में बना हुआ है। यमन में ईरान-समर्थित हूथी विद्रोहियों और सऊदी-समर्थित बलों के बीच हाल के दिनों में लड़ाई तेज़ी से बढ़ी है।

इन झड़पों को 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए संघर्ष-विराम के बाद से सबसे गंभीर माना जा रहा है; उस संघर्ष-विराम ने आठ साल के भीषण संघर्ष के बाद बड़े पैमाने पर हो रही लड़ाई को रोक दिया था। हूथी विद्रोहियों के लिए बाब-अल-मंदेब एक मुख्य केंद्र रहा है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला एक संकरा जलमार्ग है। हूथियों ने जुलाई में सऊदी जहाजों की आवाजाही रोकने की घोषणा की और बाब-अल-मंदेब के पास सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।

काशी से नौवें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल

वाराणसी, (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में बुधवार को राष्ट्रीय पोषण माह-2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य, अनुपमा जायसवाल, सावित्री ठाकुर, अंजलि राजभर सहित विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सही पोषण, देश रोशन और हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी की थीम पर आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं, बच्चों, किशोरियों और परिवारों में पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

रूस-यूक्रेन युद्ध रोकेगा भारत, जल्द होगा समझौता

कीव

रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत एक बार फिर आगे आने को तैयार है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत दोनों पक्षों के संपर्क में है और अगर युद्ध खत्म कराने में किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत लगातार यह मानता रहा है कि यह युद्ध का दौर नहीं है और किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। भारत का जोर बातचीत और कूटनीति के जरिए रास्ता निकालने पर है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 सितंबर को यूक्रेन की राजधानी की का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और राष्ट्रपति जेलस्की से भी बातचीत। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जयशंकर की यूक्रेन यात्रा का मुख्य फोकस बातचीत और कूटनीतिक की संभावनाओं को तलाशना था। बैठक में भारत ने एक बार फिर अपना वही रुख दोहराया कि युद्ध किसी समस्या का स्थाई समाधान नहीं और बातचीत के जरिए आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। भारत का मानना है कि अगर युद्ध खत्म करने में वो किसी भी तरह से मदद कर सकता है तो वह उसके लिए

तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान भारत की लगातार चली आ रही नीति को दोहराया। भारत का मानना है कि यह युद्ध का दौर नहीं और किसी भी विवाद का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। यानी भारत का संदेश साफ है। युद्ध को लंबा खींचने के बजाय उसे खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि युद्ध खत्म करने का रास्ता आखिरकार रूस और यूक्रेन को ही मिलकर तलाशना होगा। लेकिन अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने या संघर्ष को खत्म करने में भारत किसी भी तरह से मदद कर सकता है तो उसके लिए वो तैयार। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है और लगातार ऐसे विचारों और सुझावों की तलाश कर रहा है जो संघर्ष को खत्म करने की दिशा में मददगार साबित हो सकते हैं। भारत की इस भूमिका को इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अलग-अलग स्तर पर संबंध है। भारत ने शुरुआत से ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया है।

फिल्म/टीवी मनोरंजन

अक्षय खन्ना हुए दृश्यम 3 से बाहर... अब एक्टर को रिप्लेस करने पर क्या बोले जयदीप अहलावत?

बीते साल जब अक्षय खन्ना ने निर्देशक अभिषेक पाठक की दृश्यम 3 फिल्म को छोड़ा था, तो सिनेमा जगत में मामला काफी हाईलाइट रहा। अब अक्षय की जगह अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 3 में एक्टर जयदीप अहलावत ने उन्हें रिप्लेस किया है।

बुधवार को मेकर्स की तरफ से दृश्यम 3 का ट्रेलर लॉन्च किया गया है और गोवा में इसके लिए एक खास इवेंट भी रखा। जिसमें जयदीप ने अक्षय खन्ना को रिप्लेस करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना को रिप्लेस किए जाने के सवाल पर जयदीप अहलावत ने दो टूक बयान दिया है और कहा है- उस किरदार को इसके साथ जोड़ना सही नहीं है। ये एक अलग कैरेक्टर है और कहानी में नया है। मीरा देशमुख और सलगांवकर फैमिली के साथ पहली बार जुड़ रहा है। इस किरदार को अभिषेक ने बहुत गहराई के साथ लिखा है। उसके लुक और ढंग पर बारीकी से ध्यान दिया गया है। मालूम हो कि दृश्यम द कन्क्लूजन में जयदीप अहलवात क्राइम ब्रांच के ऑफिसर एसपी राजवीर सिंह तोमर की भूमिका में नजर आएंगे। अजय देवगन ने ट्रेलर लॉन्च पर बताया है कि कहानी में जयदीप के किरदार की एंट्री इस वजह से हो रही है कि पुलिस विजय सलगांवकर केस सुलझा नहीं तो अब जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। फिल्म दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना ने आईपीएस अधिकार तरुण अहलावत का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। मेकर्स ने उन्हें जहन में रखकर तीसरे पार्ट दृश्यम 3 को आगे बढ़ाया। लेकिन धुरंधर फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने दृश्यम 3 के लिए साइन अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और बाद में उनकी जगह इस फिल्म में जयदीप अहलावत को कास्ट किया गया है, जिनका किरदार अलग है। फिल्म दृश्यम 3 के ट्रेलर पर गौर किया जाए तो इस बार सस्पेंस और थ्रिल पहले दो पार्ट्स से काफी अधिक है। जिसे देख अजय देवगन की इस मूवी के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई हो गई है। बता दें कि 2 अक्टूबर 2026 को दृश्यम 3 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

मिर्जापुर- द मूवी: लेखक और निर्देशक को था किस बात का डर? रवि किशन के किरदार को बताया ग्रीन फ्लैग गैंगस्टर

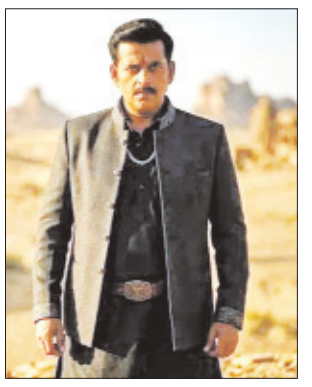

मिर्जापुर फ्रेंचाइजी में इस बार अभिनेता और सांसद रवि किशन ने एंट्री ली थी। फिल्म 'मिर्जापुर- द मूवी' में उनके किरदार बब्बन बबुआ को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस पर फिल्म के निर्देशक गुरमीत सिंह और निर्माता और लेखक पुनीत कृष्णा ने एक बातचीत बताया कि इस किरदार का फिल्म में संतुलन बनाना काफी मुश्किल था। फिल्म में गैंगस्टर बब्बन बाबू यादव का किरदार रवि किशन ने निभाया है। फिल्म के लेखत पुनीत ने एक बातचीत में कहा, 'कई युवतियों ने कहा है कि बब्बन बिल्कुल ग्रीन फ्लैग गैंगस्टर है। वह इतना समर्पित है कि अपनी मुमताज के लिए कपड़े तक सिलता है। गैंगस्टर होने की बात छोड़िए, कितने मर्द ऐसा करेंगे?' अपने इंटरव्यू में निर्देशक गुरमीत सिंह ने कहा, 'हमें तो सच में डर लगने लगा था कि क्लाइमेक्स सीन में लोग रवि किशन के प्रति इतना सहानुभूति दिखाने लगेंगे कि गुड्डू, बबलू और मुन्ना का साथ देना ही छोड़ देंगे। इसलिए हमें उसकी मौत को भी थोड़ा हल्का करना पड़ा। वह बहुत भावुक कर देने वाली घटना थी और लगभग फिल्म के खिलाफ जा रही थी। चंदू पंक्चर (सतेंद्र सोनी) की मौत को हमें जानबूझकर बहुत ज्यादा नाटकीय और क्रूर दिखाना पड़ा ताकि संतुलन बना रहे, क्योंकि लोगों को रवि किशन का किरदार बहुत पसंद आया था।' फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की मच अवेटेड फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने दर्शकों के दिल जीत लिए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की थी। पहले दिन इसने 25.75 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म ने अब तक 126.32 करोड़ का कारोबार किया है।

कियारा-सिद्धार्थ मल्होत्रा का दिखा रेट्रो अंदाज

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फैंस को एक झलक दिखाई है कि अगर वे 80 के दशक के बॉलीवुड कपल होते, तो कैसे नजर आते। जानिए पोस्ट में क्या कुछ है खास। कियारा ने हाल ही में वायरल हो रहे इंस्टाग्राम ट्रेंड को फॉलो करते हुए एआई की मदद से अपनी और पति सिद्धार्थ की एक रेट्रो तस्वीर शेयर की है। विंटेज फैशन और पुराने बॉलीवुड के अंदाज से सजी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है।

बुधवार को कियारा ने इंस्टाग्राम पर एक ढ्ढ से बनाई गई तस्वीर शेयर की, जिसमें वह सिद्धार्थ के साथ 80ह्य के अंदाज में नजर आ रही हैं। तस्वीर में सिद्धार्थ ने क्लासिक डबल-डेनिम लुक के साथ डार्क एविएटर सनग्लासेस पहने हुए हैं। वहीं, कियारा पफ स्लीव्स वाली चमकीली गुलाबी ड्रेस, बड़े हूप ईयररिंग्स और चूड़ियों में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तस्वीर में दोनों का पूरा लुक पुराने जमाने के बॉलीवुड की याद दिला रहा है। कियारा ने इस पोस्ट के

साथ सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म द वन का रोमांटिक गाना समझो ना भी लगाया है। तस्वीर सामने आते ही फैंस ने इस पर खूब प्यार बरसाया।

वर्कफ्रंट की बात करें, तो कियारा आडवाणी इन दिनों यश की फिल्म टॉक्सिक में नजर आ रही हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 14 दिनों में भारत में करीब 295 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं फिल्म दुनियाभर में 338 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

माटी गणेश एवं सिद्ध गणेश प्रतिमा निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

छिंदवाड़ा

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत बी.एस.डब्ल्यू. एवं एम.एस.डब्ल्यू. पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 'माटी गणेश एवं सिद्ध गणेश प्रतिमा निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला' का आयोजन शासकीय महाविद्यालय हर्रई में किया गया।

कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री अखिलेश जैन के निर्देशन एवं विकासखंड समन्वयक श्री आशीष नेमा के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के रूप में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के परामर्शदाता प्रकाश कुमार परतेती, स्वाति गुप्ता और अखिलेश इन्वति ने छात्र-छात्राओं को प्राकृतिक मिट्टी से गणेश प्रतिमा निर्माण की विभिन्न विधियों एवं तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य गणेश उत्सव की पूर्व तैयारी के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को मिट्टी से पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा निर्माण की कला में प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात छात्र-छात्राएं गांव-गांव जाकर ग्रामीण समुदाय, नवांकुर संस्था एवं सखी समूहों को मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित करेंगे। कार्यशाला में बताया गया कि घर पर ही प्राकृतिक मिट्टी से गणेश प्रतिमा तैयार कर उसकी पूजा-अर्चना के उपरांत प्रतिमा को गमले अथवा पॉट में विसर्जित किया जा सकता है और

उसी मिट्टी में पौधारोपण कर वृक्षों के पोषण में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार धार्मिक आस्था के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। कार्यशाला में पीओपी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई कि पीओपी पानी में आसानी से घुलता नहीं है और विसर्जन के बाद इसके अवशेष जलस्रोतों में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे जल प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से प्राकृतिक मिट्टी से बनी छोटी गणेश प्रतिमाओं को अपनाना एक बेहतर विकल्प है। प्रशिक्षण कार्यशाला में छात्र-छात्राओं ने अत्यंत उत्साह एवं रुचि के साथ मिट्टी से गणेश प्रतिमा निर्माण की कला सीखी। उन्होंने संकल्प लिया कि प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को अपने गांवों एवं समुदाय तक पहुंचाएंगे तथा अधिक से अधिक लोगों को मिट्टी के गणेश बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यशाला में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के परामर्शदाता, बी.एस.डब्ल्यू. एवं एम.एस.डब्ल्यू. के छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रशिक्षण लिया और संकल्प लिया कि वे अपने गांवों में अधिक से अधिक लोगों को माटी गणेश बनाने हेतु प्रेरित करेंगे।

शराब दुकान बम्हनी का औचक निरीक्षण

मंडला

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला श्री शैलेन्द्र चौधरी (प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी) द्वारा तहसीलदार मंडला श्री हिमांशु भलावी एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ शराब दुकान बम्हनी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने शराब दुकान में लगे कैमरों की स्थिति एवं संचालन, स्टॉक पंजी तथा उपलब्ध शराब के

स्टॉक का अवलोकन किया। साथ ही दुकान में उपलब्ध मदिरा की नकली शराब की आशंका के संबंध में जांच की गई। अधिकारियों ने दुकान संचालन से संबंधित अभिलेखों एवं व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा नियमानुसार शराब का विक्रय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जलाशयों में पानी की उपलब्धता की समीक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की बैठक आयोजित

छिंदवाड़ा

जिले में इस वर्ष अब तक औसत से कम बारिश हुई है, जिसके दृष्टिगत आगामी महीनों में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जलाशयों में उपलब्ध पानी की स्थिति, पेयजल के लिए सुरक्षित रखे जाने वाले जल और उसके बाद सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी को लेकर कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने मंगलवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक का आयोजन कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में किया गया था।

बैठक में जिले के विशेष रूप से उन जलाशयों की स्थिति पर

विस्तार से चर्चा की गई, जिनसे विभिन्न नगरीय क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि कन्हरगांव जलाशय से छिंदवाड़ा शहर, सारोठ जलाशय से मोहखेड़ जल समूह, कांगला जलाशय से दमुआ शहर, तवा जलाशय व सकरवाड़ा जलाशय से अमरवाड़ा शहर और हर्रई जलाशय से हर्रई शहर के लिए पेयजल सप्लाई की जाती है। जिनमें से कांगला और हर्रई जलाशय क्षमता के अनुरूप पूर्ण रूप से और सकरवाड़ा जलाशय 66 प्रतिशत भरा हुआ है, लेकिन अन्य जलाशयों में क्षमता के अनुरूप पानी कम है। कलेक्टर श्री नारायन ने निर्देश दिए कि जिन जलाशयों में पानी की उपलब्धता कम है, वहां 15 सितंबर की स्थिति में जल उपलब्धता के अनुरूप आगामी पूरे वर्ष के लिए व्यवस्थित जल प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार की जाए।

कलेक्टर की पहल से दो साल पुरानी छात्रवृत्ति समस्या दो दिन में हल

डीएलएड छात्रों को मिली बड़ी राहत, कलेक्टर से मिलकर जताया आभार

डिण्डोरी

प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित पहल से डाइट रंहगी के डीएलएड पूर्व छात्रों की दो वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति समस्या का महज दो दिनों में निराकरण हो गया। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पहल की, जिससे वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के छात्रों को बड़ी राहत मिली। समस्या के समाधान के बाद छात्रों ने कलेक्टर सभाकक्ष पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की और त्वरित कार्रवाई के

लिए आभार व्यक्त किया। छात्रों ने कहा कि लंबे समय से लंबित छात्रवृत्ति समस्या का इतनी शीघ्रता से समाधान होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के साथ ही राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के अधिकारियों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया। त्वरित निराकरण से छात्रों में जिला प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।

चित्रकूट बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय

बांटी मदद और बच्चों में जगाया अफसर बनने का सपना

सतना

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को सतना जिले के चित्रकूट पहुंचे और मंदाकिनी की बाढ़ ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों का कुशलक्षेम पूछा, उनकी परेशानियां सुनीं और भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरे का सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया, जब मंत्री राहत सामग्री बांटने के बीच बच्चों के पास पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बातचीत स्वयं उनके बीच बैठकर स्कूल बैग, कॉपी-किताबें वितरित कीं। मंत्री ने बच्चों से पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहते हैं। जब एक बच्चा अपने भविष्य का लक्ष्य स्पष्ट नहीं बता पाया तो विजयवर्गीय ने उसे हौसला देते हुए अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण

दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने सफर की शुरुआत पार्षद के रूप में की, इसके बाद विधायक बने और आज मंत्री हैं। बच्चों से उन्होंने कहा कि अच्छी पढ़ाई करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। इस दौरान उन्होंने सतना कलेक्टर का उदाहरण देते हुए बच्चों से कहा कि मेहनत के बल पर आज वह कलेक्टर हैं। मंत्री का बच्चों से यह संवाद बाढ़ की पीड़ा के बीच उन्हें भविष्य के सपने दिखाने वाला नजर आया।

उजड़े आशियानों के लिए सरकार की मदद - बाढ़ से जिन परिवारों के घर पूरी तरह प्रभावित हुए हैं, उनमें से पांच परिवारों को मंत्री ने सरकार की ओर से 1 लाख 20 हजार की सहायता राशि के चेक वितरित किए। इसके अलावा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार के लिए चेक दिए गए। प्रभावित परिवारों को सहायता पाने वाले हितग्राहियों को भी 50 किलो राशन, कंबल और अन्य राहत सामग्री भी वितरित की गई। मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से राहत व्यवस्था की जानकारी ली और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया।

दीनदयाल रसोई पहुंचे, खुद खाई पूड़ी-सब्जी - राहत वितरण के बाद विजयवर्गीय नगर परिषद द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई पहुंचे। यहां बाढ़ प्रभावितों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता देखने के लिए उन्होंने स्वियं पूड़ी-सब्जी खाई। नगर अध्यक्ष ने मंत्री को बताया कि 30 अगस्त से बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुबह-शाम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

उद्यमियों से सीधा संवाद, कलेक्टर ने कहा :मेहनत से छोटा उद्यम भी बन सकता है बड़ा कारोबार

डिण्डोरी

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत मंगलवार को रेस्ट हाउस डिंडौरी में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में ''उद्यम संवाद'' आयोजित किया गया। संवाद में जिले के छोटे-बड़े उद्यमों से जुड़े उद्यमियों एवं विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। उद्यमियों ने अपने व्यवसाय एवं उद्यम की जानकारी साझा करते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त राशि, सब्सिडी एवं अन्य सुविधाओं से हुए लाभ की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने उद्यमों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार के संबंध में भी बताया।

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने कहा कि दैनिक जीवन की

आवश्यकताओं की पूर्ति और जिले के आर्थिक विकास के लिए उद्यमों को बढ़ावा देना जरूरी है। शासन द्वारा उद्यमियों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से आर्थिक सहायता, भूमि एवं सब्सिडी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी उद्यम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत और लगन से छोटा उद्यम भी बड़े व्यवसाय का रूप ले सकता है। उद्यमी निरंतर मेहनत और नवाचार के साथ आगे बढ़ें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कलेक्टर ने उद्यमियों से कहा कि उद्यम संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या सामने आती है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि उसका समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उद्यमियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिव्यांशु चौधरी ने भी विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से उद्यमियों को मिलने वाले लाभ एवं सुविधाओं की जानकारी दी। उद्यम संवाद में पुलिस अधीक्षक श्री आशीष खरे, वनमंडलाधिकारी श्री अशोक सोलंकी सहित उद्यमिता से संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जिले के उद्यमी उपस्थित रहे। संवाद के दौरान उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए और शासन की योजनाओं से मिले सहयोग को जिले में स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने में उपयोगी बताया।

4 हजार 45 किलो महुआ लाहन नष्ट

19 प्रकरणों में 150 लीटर कच्ची शराब और 75 पाव देशी-अंग्रेजी शराब जब्त

मंडला

जिले में अवैध कच्ची एवं जहरीली शराब के निर्माण, संग्रहण और विक्रय के खिलाफ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश रघुवंशी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के लिए तैयार 4 हजार 45 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया। वहीं 19 प्रकरण दर्ज कर 150 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 75 पाव देशी-अंग्रेजी शराब जब्त की गई। महाराजपुर पुलिस ने एसडीओपी श्री पीयूष मिश्रा के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी निरीक्षक डॉ. जयसिंह यादव के नेतृत्व में ग्राम मड़ईजर क्षेत्र में नालों के किनारे संचालित अवैध शराब निर्माण अड्डों पर दबिश दी। पांच अड्डों की जांच में 385 प्लास्टिक डिब्बों में करीब 3 हजार 850 किलो महुआ लाहन मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। शराब निर्माण में प्रयुक्त बर्तन, चूल्हे और अन्य सामग्री भी नष्ट की गई। नष्ट लाहन की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई गई। कोतवाली पुलिस ने बड़ी खैरी, गोंझी एवं बड़ी गोंझी क्षेत्र में 8 प्रकरणों में 89 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। बीजाडांडी पुलिस ने चौरई, पौड़ी रैयत एवं बीजाडांडी में कार्रवाई करते हुए 4 प्रकरणों में 36 लीटर कच्ची शराब तथा 3 प्रकरणों में 75 पाव देशी-अंग्रेजी शराब जब्त की। साथ ही करीब 135 किलो महुआ लाहन नष्ट किया गया। हिरदेनगर चौकी पुलिस ने रामनगर और चौगान क्षेत्र में 4 प्रकरणों में 25 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की तथा 60 लीटर महुआ लाहन नष्ट किया। पुलिस के अनुसार कार्रवाई में संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

संबल योजना के लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर श्री तिवारी सख्त सीएम हेल्पलाइन

अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता के प्रकरणों की समीक्षा, 57 लंबित मामलों की जांच के निर्देश

कटनी

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में ग्राम पंचायतों के कार्यों के साथ-साथ संबल योजना के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। उन्होंने संबल योजना के अंतर्गत विभिन्न निकायों में लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों, अनुग्रह सहायता तथा अंत्येष्टि सहायता के प्रकरणों की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, जिला श्रम अधिकारी श्री केबी मिश्रा,सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह की मौजूदगी रही। कलेक्टर श्री तिवारी ने अनुग्रह सहायता के लंबित अपीलीय प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एसडीएम कटनी को इनका शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ढीमरखेड़ा जनपद में लंबे समय से लंबित दो प्रकरणों पर भी कलेक्टर ने विशेष गंभीरता दिखाई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दोनों प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।100

दिवस से अधिक लंबित शिकायतों पर विशेष फोकस बैठक में कलेक्टर ने 100 दिवस से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित निकायों के अधिकारियों को लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों की संख्या कम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।अंत्येष्टि सहायता के 57 प्रकरणों की होगी विस्तृत जांच नगर निगम कटनी अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता के 57 लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री तिवारी ने श्रम अधिकारी कटनी को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों की विस्तृत जांच कर वस्तुस्थिति सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पात्रता, दस्तावेजों एवं प्रकरणों में हुई देरी के कारणों की जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री तिवारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबल योजना शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका सीधा लाभ श्रमिक एवं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है। इसलिए योजना से संबंधित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर शासन की सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आबकारी अमले की बड़ी कार्रवाई, 1.32 लाख रुपए से अधिक की अवैध मदिरा जब्त

कटनी

जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी अमले ने वृत्त स्लीमनाबाद एवं वृत्त बहोरीबंद क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा एवं महुआ लाहन जब्त किया। आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री मंशा राम उइके के नेतृत्व में ग्राम सिहुड़ी, कंचनपुर, बरही, साडा एवं पटना में कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान टीम ने लगभग 1265 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 41 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद कर विधिवत जब्त की। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 1 लाख 32 हजार 650 रुपए से अधिक बताई गई है। कार्रवाई के दौरान महुआ लाहन के नमूने विधिवत लिए गए तथा शेष महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। अवैध मदिरा के संबंध में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 34(1)(च) के तहत कुल 16 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। इस कार्रवाई में वृत्त बहोरीबंद प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक अतुल कुटार, सीमा देवी कोल तथा मुख्य आरक्षक राम सिंह, राजेश गौंटिया, वीणा ब्रह्मवंशी, चन्द्रप्रकाश त्रिपाठी एवं नव नियुक्त आबकारी आरक्षक रवि भुमिया और सिमरन उर्मलिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सिवनी जिले के छपारा में पुलिस थाने के बगल में सट्टे का महाजाल, जिम्मेदार मौन-जनता परेशान

स्वतंत्र मत। छपारा / सिवनी जिले के छपारा नगर में इन दिनों कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है। नगर में जुआ-सट्टा का अवैध कारोबार चरम सीमा पर पहुंच गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा काला कारोबार छपारा पुलिस थाने से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर बेखौफ चल रहा है।

दिन-दहाड़े कट रही पर्चियां

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छपारा के मुख्य बाजार, बस स्टैंड और थाने के आसपास के इलाकों में खुलेआम सट्टे की पर्चियां काटी जा रही हैं। सुबह से शाम तक सटोरियों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस की गाड़ियां रोज इसी रास्ते से गुजरती हैं, लेकिन इस अवैध धंधे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

बर्बाद हो रहे हैं गरीब परिवार

इस जुआ-सट्टे की लत ने सैकड़ों परिवारों को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। गरीब मजदूर, किसान और युवा वर्ग अपनी खून-पसीने की कमाई चंद मिनटों में गंवा रहे हैं। कई घरों में इस वजह से रोज झगड़े हो रहे हैं। युवा पीढ़ी मेहनत छोड़कर रातों-रात अमीर बनने के इस झांसे में फंसती जा रही है।

पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल

थाने के इतने करीब इतना बड़ा अवैध कारोबार चलना कई सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि बिना किसी संरक्षण के यह संभव नहीं है। लोगों का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं या आंखें मूंद लें, तो आम आदमी न्याय के लिए कहां जाए।

वही पुलिस प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान न दिया जाना संदिग्ध माना जा रहा है। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, या जानबूझकर अनदेखी की जा रही है, यह बड़ा सवाल है।

एसपी से कार्रवाई की मांग

छपारा के जागरूक नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सिवनी पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। थाने के आसपास चल रहे इस सट्टा कारोबार पर तत्काल छापामार कार्रवाई कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि नगर में कानून का राज स्थापित हो सके।

गांवों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं, सीएमएचओ-डीपीओ ने किया निरीक्षण

सिवनी। स्वतंत्र मत। जिला कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के मार्गदर्शन में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं को गांवों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने मैदानी क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज दुबे एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज लारोरकर ने विकासखंड गोपालगंज के आंगनवाड़ी केंद्र राहीवाड़ा एवं सोनाडोंगरी में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का संयुक्त निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने केंद्रों पर उपस्थित गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखी। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण परामर्श तथा बच्चों की वृद्धि की निगरानी की जानकारी ली गई। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को संभावित प्रसव से लगभग 15 दिन पूर्व अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देने के निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन, रक्त शर्करा, एल्बुमिन एवं सिकल सेल एनीमिया की जांच के साथ वजन एवं ऊंचाई की माप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में भारतेंदु का योगदान अविस्मरणीय

सिवनी। हिंदी पुनर्जागरण के प्रणेता और युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 176 वीं जयंती का आयोजन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस के हिंदी विभाग में किया गया. कार्यक्रम में प्राध्यापक वक्ताओं के व्याख्यान के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भारतेंदु के कालजयी व्यक्तित्व और कृतित्व को जाना-समझा और उनके अविस्मरणीय योगदान को याद किया।

भारतेंदु हरिश्चंद्र के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी प्राचार्य डॉ सविता मसीह ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग प्रवर्तक साहित्यकार थे. उन्होंने हिंदी की कई विधाओं में अपने लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया. बताया कि 35 वर्ष के छोटे-से जीवन काल में उन्होंने विपुल साहित्य लेखन किया. कहा कि भारतेंदु की साहित्यिक रचनाओं पर आज भी शोध कार्य किया जा सकता है।

विशेष वक्ता के रूप में हिंदी विभाग के प्रोफेसर सत्येन्द्र शेन्डे ने कहा कि काशी विश्व की सबसे पवित्र नगरी है. ऐसे पावन स्थान में जन्म लेकर भारतेंदु जी ने अपने लेखन से खड़ी बोली हिंदी के साहित्य को नई दिशा और दशा प्रदान की. उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए हिंदी साहित्य की एक पूरी अवधि भारतेंदु युग के नाम से जानी जाती है. कहा कि अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटक आज भी प्रासंगिक हैं. उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन भारत का यथार्थ चित्रित किया है. अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉ मानसिंह बघेल ने कहा कि भारतेंदु जैसे साहित्यकार कभी-कभार ही जन्म लेते हैं. भारतेंदु की लिखी हुई कई कविताएं और दोहे आज भी गांव के अनपढ़ लोगों को याद हैं. कार्यक्रम का संचालन करते हुए जन भागीदारी शिक्षक अमितोष ने भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार से बताया. कार्यक्रम में डॉ. मीडिया कुमरे, डॉ. रामकुमार नायक, डॉ मनोज टेंभरे, छाया राय, डॉ नीलेश्वरी बिसेन, ओमप्रकाश जैन तथा महाविद्यालय परिवार के प्राध्यापकों और शिक्षकों सहित एम ए और बीए कक्षाओं के छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

सिमरिया में मंदिर से लगी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत

सिवनी। स्वतंत्र मत। लखनवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खेरीटेक के ग्राम सिमरिया में मंदिर से लगी भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कब्जे का विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज एवं अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की धमकी दी गई। ग्रामीणों ने जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार, विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उन्होंने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया था। ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम के सामने भी संबंधित व्यक्ति द्वारा कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने लखनवाड़ा थाना पहुंचकर लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। इसी मामले में ग्राम की एक महिला ने भी गाली-गलौज, अपशब्दों के साथ मारपीट की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। महिला सहित दर्जनों ग्रामीण महिला-पुरुष लखनवाड़ा थाना पहुंचे और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की।

मंदिर से लगी भूमि पर मांस बिक्री का आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंदिर से लगी भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर मांस की बिक्री की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर मंदिर परिसर एवं उससे लगी भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

हल्का पटवारी की लापरवाही भी सामने आई

मामले में उप पुलिस अधीक्षक सी.के. सिरामे ने बताया कि इस मामले में हल्का पटवारी की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि कल तहसीलदार सहित राजस्व विभाग एवं पुलिस बल की उपस्थिति में मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

मंदिर परिसर को भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने मंदिर परिसर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की उम्मीद जताई है।

आज संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती का समापन समारोह

सिवनी। स्वतंत्र मत। स्वतंत्र मत। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं कलश यात्रा का समापन समारोह 10 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार जिले में 20 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा 20 अगस्त 2026 से कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। कलश यात्रा का शुभारंभ रविदास मंदिर, चौक वार्ड, सिवनी से किया गया। यह कलश यात्रा कुरई, बरघाट, केवलारी, धनौरा, घंसौर, लखनादौन एवं छपारा होते हुए 10 सितंबर 2026 को शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, लखनादौन में पहुंचकर संपन्न होगी। समापन अवसर पर संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विकासखंड अधिकारी, लखनादौन को प्रभारी नियुक्त किया गया है।

समापन समारोह में जिले के संत शिरोमणि रविदास समाज के अनुयायियों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सभी सामाजिक अनुयायियों एवं नागरिकों से 10 सितंबर को आयोजित समापन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है।

कुरई के विकास कार्यों से जुड़े लंबित भूमि प्रकरणों पर राकेश सनोडिया ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

13 सितंबर तक संयुक्त निरीक्षण एवं अंतिम निर्णय की मांग, 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान

कुरई/सिवनी। ग्राम कुरई में विकास कार्यों और जनसुविधाओं के विस्तार से जुड़े भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों को लेकर जिला पंचायत सिवनी के उपाध्यक्ष राकेश सनोडिया ने प्रशासन को पत्र सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 13 सितंबर 2026 तक संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक एवं स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट एवं अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 14 सितंबर से सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय कुरई के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

एसडीएम कुरई को दिए पत्र में राकेश सनोडिया ने उल्लेख किया है कि ग्राम कुरई के विकास एवं जनसुविधाओं के विस्तार के लिए करीब दो वर्षों से कलेक्टर सिवनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, वनमंडलाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं वन परिक्षेत्राधिकारी कुरई सहित संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन एवं पत्राचार किया जा रहा है। इसके बावजूद संबंधित प्रकरणों का निराकरण नहीं होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

वन विभाग कार्यालय के समीप भूमि का मामला

पत्र में ग्राम कुरई एवं पिंडकापार की राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 105/1 सहित अन्य संबंधित भूमि का उल्लेख किया गया है। पत्र के अनुसार वन विभाग के भवन, कार्यालय, मार्ग एवं आवश्यक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त पर्याप्त रिक्त भूमि उपलब्ध है। इस भूमि पर जिला पंचायत की निधि से सामुदायिक पार्क, गार्डन एवं ओपन जिम निर्माण प्रस्तावित एवं स्वीकृत होने की बात कही गई है। हालांकि, पत्र में आरोप लगाया गया है कि उक्त भूमि पर अनधिकृत रूप से तार एवं बांस की फेंसिंग कर अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। दूसरे प्रकरण में कुरई बस स्टैंड के समीप वन विभाग के पुराने एवं जर्जर शासकीय क्वार्टरों की भूमि का मामला उठाया गया है। पत्र के मुताबिक इन भवनों को लोक निर्माण विभाग द्वारा कंडम घोषित किया जा चुका है। परिसर के आगे और पीछे उपलब्ध भूमि पर वर्तमान में ग्रामीणों एवं कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। राकेश सनोडिया ने इस भूमि पर नवीन बस स्टैंड, सुलभ शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। पत्र के अनुसार इस संबंध में पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिए गए, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

13 सितंबर तक निर्णय नहीं तो आंदोलन

राकेश सनोडिया ने कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनमंडलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों से दोनों प्रकरणों की संयुक्त बैठक एवं स्थल निरीक्षण कर 13 सितंबर तक अंतिम निर्णय सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर 14 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से एसडीएम कार्यालय कुरई के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति निर्मित होने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों की होगी।

सिवनी महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार झाड़े समाज का भुजलीया मिलन समारोह संपन हुआ

सिवनी। स्वतंत्र मत। महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष संजय सोनी (पप्पू) द्वारा बताया गया कि 6 सितंबर को सिवनी स्वर्णकार झाडे समाज के तत्वाधान में में आगामी कार्यक्रम को लेकर व समाज के उत्थान के लिए क्या कार्य किया जाए इस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे जिला महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के समस्त पदाधिकारीयों की नियुक्ति सर्व सम्मति से की गई।

महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज सिवनी महिला जिला अध्यक्ष वंदना सोनी जी को व जिला पदाधिकारो की समस्त कार्यकारणी गठित गई साथ ही साथ महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के नगर अध्यक्ष नारायण सोनी जी को सर्व सम्मति से निर्विरोध चुना गया व नगर कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जिला महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमती वंदना सोनी पापड़े, उपाध्यक्ष श्रीमती सविता सोनी येरपुडे, भारती सोनी येरपुडे ,रीना सोनी निनावे , कोषाध्यक्ष शीतल सोनी कारेमोरे, सचिव संध्या सोनी पापडे, सह सचिव कल्पना सोनी टेटे, प्राचार मंत्री सरिता सोनी डांगरे, आराधना पांडे, संगठन मंत्री छाया सोनी गुरव, मंत्री मनीषा पथिक, सरिता डोमने, संरक्षक मंडल पदमा भुजाडे, पुष्पा बांगरे, पदमा येरपुडे, मंजू निनावे, अर्चना पापड़े,सीमा पापड़े,सदस्य सरला टेटे, कुसुम अरमरकार, हेमवती गुरव, उर्मिला पथिक, प्रभा सोनी, मीरा पापड़े, सुधा निनावे, अलका येरपुडे, मधु टेटे, को सभी सामाजिक महिलाओं ने निर्विरोध चुना गया इसी तरह जिला उपाध्यक्ष गौतम सोनी, जिला प्रचार मंत्री अरविंद सोनी, जिला प्रचार मंत्री सुरेश सोनी, जिला संगठनमंत्री वरिष्ठ चमरूलाल सोनी चक्की खमरिया, जिला संगठन मंत्री सोहन सोनी, जिला मंत्री स्वरूपानंद सोनी, जिला संरक्षक मंडल पूनम जी सोनी ,मकरन सोनी ,चंदन सोनी, रतिराम सोनी, सेवक सोनी को चुना गया इसी तरह नगर कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई जिसमें नगर अध्यक्ष नारायण सोनी, उपाध्यक्ष संतोष सोनी, उपाध्यक्ष संदेश सोनी, सचिव चंदन ढोमने,सह सचिव अखिल सोनी, संगठन मंत्री प्रावीण सोनी, प्रचार मंत्री प्रमोद सोनी एवं नगर सदस्य के रूप में राजेंद्र सोनी ,महेश सोनी, मनीष सोनी, संदीप सोनी ,उत्तम सोनी को सर्वसम्मति से चुना गया आपस में एक दूसरो को भुजालिया आदान प्रदान कर एक दूसरों की गले लगे एवं मिलन समारोह मनाया वा सभी ने मिल कर वृक्षारोपण किया जिस में भारी संख्या में समाज के वरिष्ठ जान समाज के समस्त पदाधिकारी महिला पुरुष वा युवा साथी उपस्थित रहे ।

दिल की बात कार्यक्रम में उपस्थित हुए विधायक ठाकुर रजनीश

3100 का धान और 2700 का गेहूं देने का वादा पूरा नहीं हुआ- विधायक रजनीश सिंह ठाकुर ने सरकार को घेरा

रूमाल में कांग्रेस की बैठक, विधायक रजनीश सिंह ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना

उगली। सिवनी जिले की जनपद पंचायत केवलारी के उप तहसील उगली अंतर्गत रूमाल रेस्ट हाउस में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उगली की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत एवं सक्रिय बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक रजनीश सिंह ठाकुर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पूज्य महात्मा गांधी एवं महान राजा भोज के नाम से निर्मित सभा मंच का लोकार्पण भी किया गया। लोकार्पण के दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने संगठन को मजबूत बनाने और कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने पर विचार-विमर्श किया।

मैं विपक्ष का विधायक हूं, फिर भी क्षेत्र की बात रखता हूं

दिल की बात कार्यक्रम के तहत विधायक रजनीश सिंह ठाकुर ने कहा कि वे विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री का क्षेत्र में आगमन होता है तो वे क्षेत्र की समस्याओं को उनके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नहरों में सीमेंटीकरण सहित किसानों और आम लोगों से जुड़े कई मुद्दों को लगातार उठाया जा रहा है। विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना और सम्मान निधि के नाम पर सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। महंगाई के माध्यम से आम जनता से उससे कई गुना अधिक पैसा वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी विधायक निधि से क्षेत्र में विकास कार्य स्वीकृत होते हैं, लेकिन सांसद क्षेत्र में आकर उन्हीं कार्यों का भूमि पूजन कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्षेत्र के विकास के लिए सभी जरूरी कार्य करवाने का प्रयास किया जाता। विधायक रजनीश सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों से आत्मीयता से जुड़ते हुए कहा कि उनका और जनता का परिवार जैसा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि उनसे कोई भूल-चूक या गलती हुई हो तो उन्हें माफ कर दें।

कार्यालय संभागीय अधिकारी
संभाग क्रमांक -12 घंटाघर
नगर निगम, जबलपुर

पत्र क्र.सं.अधि/सं.क्र.12/2026-27/एम-23
दिनांक 21/08/2026

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अंकिता यादव पति श्री चंद्रकांत यादव ने मकान नं. 530 वार्ड पं. मदन मोहन मालवीय कुल क्षेत्रफल 805 व.फु. निर्मित क्षेत्रफल 1300 व.फु. विक्रयपत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दियाहै, जिस किसी व्यक्ति को उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्र. 12 घंटाघर में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

संभागीय अधिकारी
संभाग क्रमांक-12 घंटाघर
नगर निगम, जबलपुर

आम सूचना

मैं श्रीमति कला सोनकर पति स्व. श्री ज्ञानचंद्र सोनकर उम्र लगभग 68 वर्ष स्थाई पता-802, बड़ी ओमती जबलपुर वर्तमान पता- मधुवन कॉलोनी तिलहरी जबलपुर मेरे स्वामित्व के 3 मकान, मकान नं. क्रमशः 802, 803, एवं 740 बड़ी ओमती पंडित बाल गंगाधर तिलक वार्ड जबलपुर में स्थित है। जिसमें से मकान नं. 740 किराये पर चलता है जिसका किराया मुझे प्राप्त होता है। तथा मेरे नाम से कलाश्री केबल नेटवर्क संचालित होता है। बड़ी ओमती के आसपास केबल कनेक्शन का किराया लेने की मैं अधिकारी हूं। मेरे द्वारा कुछ दिन पूर्व अपने पोते अनीश व ऋषि सोनकर को केबल का किराया वसूलने के लिए कह दिया था जो अनीश सोनकर ने केबल का किराया मुझे न देकर स्वयं के उपयोग मे खर्च कर लिया है इसलिए इस आम सूचना के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे केबल नेटवर्क का किराया एवं मकान का किराया संबंधित व्यक्ति अनीश सोनकर को न देवें। आज दिनांक से केबल नेटवर्क का किराया और मकान किराया वसूल करने के लिए मैं अपने पुत्र अनिल सोनकर एवं विकास उर्फ चिंटू सोनकर को अधिकृत कर रही हूं। मेरे पुत्रों को ही मकान किराया और केबल नेटवर्क किराया राशि को वसूल करने का अधिकार होगा अनाधिकृत व्यक्ति को किराया भुगतान करने पर संबंधित पक्षकार स्वयं उत्तरदायी होगा।

जबलपुर
दिनांक- 08.09.2024
श्रीमति कला सोनकर
र.नं. 2134 मो.नं. - 9479968932

बकाया कर चुकाने निगमायुक्त ने की अपील

नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को मिलेगी विशेष छूट

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। करदाताओं और पात्र हितग्राहियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने राजस्व वसूली अभियान के साथ-साथ प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। निगमायुक्त श्री अहिरवार ने 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का पूरा लाभ करदाताओं तक पहुँचाने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक करदाताओं को प्रेरित किया जाए ताकि वे अपने लंबित संपत्तिकर, जलकर और अन्य बकाया देयों का निपटारा कर शासन द्वारा दी जा रही छूट व सुविधाओं का लाभ ले सकें।

12 सितंबर को जलापूर्ति रहेगी प्रभावित

सब-मदार छल्ला पानी की टंकी में चलेगा सुधार कार्य

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। कार्यपालन यंत्री जल कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नर्मदा जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 55 एम.एल.डी. ललपुर जल शोधन संयंत्र से जुड़ी मदार छल्ला उच्चस्तरीय पानी की टंकी के लीकेज हेतु ग्राउटिंग का कार्य किया जा रहा है। सुधार कार्य के चलते उक्त टैंक से दिनांक 10 सितम्बर 2026 को प्रातःकालीन से लेकर दिनांक 12 सितम्बर सायंकालीन तक जलापूर्ति प्रभावित हरेगी। उक्त अतिमहत्वपूर्ण कार्य के चलते क्षेत्रीय नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, जल प्रभारी दामोदर सोनी एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने खेद व्यक्त किया है।

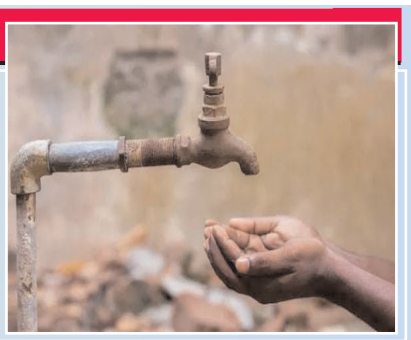

नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला : मप्र हाईकोर्ट ने 189 सूटेबल कॉलेजों के छात्रों को दी राहत

डुप्लीकेट फैकल्टी पर लगाया 3 लाख रुपए जुर्माना

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

मप्र में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संचालन में हुए फर्जीवाड़े से जुड़े मामलों में मप्र हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने 189 सूटेबल नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने और पहले परीक्षा दे चुके छात्रों के रिजल्ट जारी करने की अनुमति दी है। हालांकि डुप्लीकेट टीचिंग फैकल्टी वाले कॉलेजों को प्रति डुप्लीकेट फैकल्टी 3 लाख रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। जुर्माना जमा करने के बाद ही संबंधित कॉलेजों को उपयुक्त माना जाएगा और उनके छात्रों की परीक्षाएं आयोजित हो सकेंगी। मप्र हाईकोर्ट ने प्रत्येक संबंधित कॉलेज को परिसर या आसपास 50 पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने के भी निर्देश दिए हैं। पौधारोपण की तस्वीरें निसर्ग ऐप पर अपलोड करनी होंगी। इस मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एड विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित सभी संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी।

रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जमा करना होगा जुर्माना

सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में सूटेबल पाए गए 119 कॉलेजों और डिफिशिएंट पाए गए 153 कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी की डुप्लीकेसी मिली है। वहीं, 35 सूटेबल कॉलेज ऐसे हैं, जहां डुप्लीकेट फैकल्टी नहीं मिली। हाईकोर्ट ने डुप्लीकेट फैकल्टी वाले कॉलेजों के लिए प्रति फैकल्टी 3 लाख रुपए जुर्माना तय किया है। इसमें 2 लाख रुपए एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और एक लाख रुपए जुवेनाइल जस्टिस फंड में जमा करने होंगे। कॉलेजों को यह राशि एक महीने के भीतर जमा करनी होगी। इसके बाद संबंधित कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

50 पौधे लगाने और देखरेख करने के निर्देश

मप्र हाईकोर्ट ने संबंधित कॉलेजों को अपने परिसर या आसपास 50 पौधे लगाने के निर्देश भी दिए हैं। कॉलेजों को इन पौधों की पेड़ बनने तक देखरेख करनी होगी। पौधारोपण के बाद उसकी तस्वीरें निसर्ग ऐप पर अपलोड करनी होंगी। कोर्ट के इस निर्देश का पालन संबंधित कॉलेजों को परीक्षा संबंधी राहत हासिल करने की प्रक्रिया के तहत करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के छात्रों को राहत मिलेगी। जिन छात्रों ने पहले परीक्षा दे दी है, उनके रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे। वहीं, पात्र कॉलेजों के जिन छात्रों की परीक्षाएं रुकी हुई थीं, उनके लिए परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है।

एमपीएनआरसी को दी सख्त हिदायत

मप्र हाईकोर्ट ने मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को नए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देते समय पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉलेजों के निरीक्षण और तय मापदंडों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर संबंधित नियामक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने नए मान्यता प्राप्त सभी नर्सिंग कॉलेजों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आलोक बागरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट के सामने कई तथ्य रखे। हाईकोर्ट ने मान्यता प्रक्रिया में हुई गड़बडिय़ों को लेकर संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

जबलपुर से महानगरों के लिए जल्द शुरू की जाएं हवाई सेवाएं

घटती वायु सेवाओं को लेकर फेडरेशन ने इंडिगो एयरलाइन को सौंपा ज्ञापन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

फेडरेशन ऑफ मप्र चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जबलपुर की घटती एवं सीमित वायु सेवाओं को लेकर इंडिगो एयरलाइन के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। बैठक में फेडरेशन ने जबलपुर की औद्योगिक, व्यापारिक, पर्यटन एवं निवेश संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जबलपुर की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव एवं मांगें रखीं। फेडरेशन अध्यक्ष हिमांशु खरे ने कहा कि जबलपुर मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण संभागीय मुख्यालय होने के साथ औद्योगिक, शैक्षणिक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है। वर्तमान में जबलपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इंदौर एवं कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए वायु सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि पूर्व में जबलपुर अहमदाबाद, पुणे एवं चेन्नई से भी जुड़ा हुआ था। फेडरेशन ने मांग की कि जबलपुर से पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई एवं पटना के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएं। बैठक में इंडिगो की ओर से डायरेक्टर सेल्स प्रीतम चक्रवर्ती ने बताया कि इंडिगो की जबलपुर से बेंगलुरु की फ्लाइट को बोइंग विमान सेवा में परिवर्तित किए जाने की योजना है तथा इसे चेन्नई तक कनेक्ट किया जाएगा। इससे जबलपुर से चेन्नई की यात्रा लगभग 5 घंटे में पूरी हो सकेगी। इससे जबलपुर की दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत होने की संभावना है। फेडरेशन का मानना है कि इन शहरों के लिए सीधी उड़ानें प्रारंभ होने से उद्योगपतियों, व्यापारियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों एवं आम यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में निवेश, व्यापारिक गतिविधियों एवं अंतरराज्यीय संपर्क को भी गति मिलेगी।

300 से 500 किलोमीटर की परिधि वाली उड़ानों का विस्तार - फेडरेशन ने इंडिगो प्रबंधन को सुझाव दिया कि जबलपुर के आसपास लगभग 300 से 500 किलोमीटर की परिधि में आने वाले शहरों तक संचालित हो रही उपयुक्त उड़ानों को जबलपुर तक बढ़ाया जाए। इससे मौजूदा रूट के विस्तार के माध्यम से जबलपुर की हवाई कनेक्टिविटी को शीघ्र बढ़ाया जा सकेगा। फेडरेशन अध्यक्ष ने बैठक में जबलपुर में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से बढ़ रहे विमानन क्षेत्र के कारण प्रशिक्षित पायलटों एवं अन्य एविएशन प्रोफेशनल्स की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। यदि जबलपुर में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाता है, तो इससे मप्र के युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

जिला शालेय क्रॉसकंट्री रेस का आयोजन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जिला शिक्षा अधिकारी गौतम बर्वे एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी मधुमिता हाजरा के मार्गदर्शन में आज प्रातः 6 बजे जिला शालेय क्रॉस कंट्री रेस रांझी गोकलपुर से 19 वर्ष बालक बालिका की क्रमशः 5 किलोमीटर बालकों के लिए और 3 किलोमीटर बालिकाओं के लिए कराई गयी। जिसमे 19 वर्ष बालकों में प्रथम तरुण श्रीवास द्वितीय करन लोधी और तृतीय साहिल यादव रहे और साथ ही 19 वर्ष बालिकाओं में प्रथम लक्ष्मी बेन द्वितीय रीना लोधी तृतीय शालिनी चौधरी रहे। क्रॉस कंट्री रेस संपन्न कराने में रॉबर्ट मार्टिन, मीनुकान्त शर्मा, चंद्रशेखर स्वामी, दिनेश गोंड, राजेश सहारिया, सुधीर अवधिया, सुरेंद्र चौधरी, अशोक राय सभी ने उपस्थित रहकर रेस संपन्न कराई ।

जबलपुर-गया के बीच चलेगी 3-3 ट्रिप पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। पितृपक्ष के अवसर पर गया में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 01701/01702 जबलपुर-गया-जबलपुर पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन को 03-03 ट्रिप चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेनों के लिए 10 सितम्बर 2026 से कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों एवं ऑनलाइन आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से आरक्षण कराया जा सकता है। रेल यात्री अग्रिम आरक्षण कर अपनी सीट की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सुविधाजनक एवं सुगम यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। गाड़ी संख्या 01702 गया-जबलपुर एक्सप्रेस स्पेशल दिनांक 28 सितम्बर, 03 एवं 08 अक्टूबर को गया स्टेशन से दोपहर 15.30 बजे प्रस्थान करेगी।

एमपीपीजीसीएल की जल विद्युत इकाइयों ने पकड़ी रफ्तार

मानसून की अच्छी बारिश का मिला लाभ, अगस्त में लक्ष्य से 42 मिलियन यूनिट अधिक उत्पादन

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। प्रदेश में मानसून की शुरुआती सुस्ती के बाद हुई अच्छी बारिश का मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की जल विद्युत इकाइयों को सीधा लाभ मिला है। कंपनी के जल विद्युत गृहों ने अगस्त में निर्धारित 339 मिलियन यूनिट के मुकाबले 380.90 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर लक्ष्य से करीब 42 मिलियन यूनिट अधिक उत्पादन दर्ज किया। इस दौरान जल विद्युत इकाइयों का प्लांट उपलब्धता कारक 83.40 प्रतिशत रहा। कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने कहा कि जल विद्युत गृहों में समय रहते की गई तकनीकी तैयारी, रणनीतिक योजना और परिचालन दक्षता के कारण मानसून से उपलब्ध जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सका। उन्होंने कहा कि कंपनी ने मौसम की अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय पहले से तैयारियों को प्राथमिकता दी, जिसका परिणाम लक्ष्य से अधिक उत्पादन के रूप में सामने आया।

लक्ष्य से 20 मिलियन यूनिट आगे चल रही इकाइयां - 'रेडीनेस फर्स्ट' रणनीति से वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य पार के अंतर्गत प्रदेश में संचालित 10 जल विद्युत गृहों की कुल स्थापित क्षमता 915 मेगावाट है। चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त माह के अंत तक 963 मिलियन यूनिट के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 983 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो चुका है। यानी कंपनी की जल विद्युत इकाइयां अब तक निर्धारित लक्ष्य से 20 मिलियन यूनिट आगे चल रही हैं। कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष में जल विद्युत गृहों के संचालन की रणनीति को 'रेडीनेस फर्स्ट' दृष्टिकोण पर केंद्रित किया है।

अवैध क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा, मचा हड़कंप

सिहोरा (स्वतंत्र मत)। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने साई मंगलम कॉलोनी वार्ड नंबर 13 के मकान नंबर 1 खितौला स्थित एक कथित अवैध क्लीनिक पर छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार क्लीनिक प्रीति केवट द्वारा संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में दवाइयां, इंजेक्शन और अन्य चिकित्सा सामग्री मिली है। सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सरकारी इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है कि वे क्लीनिक तक कैसे पहुंचे और उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था। क्लीनिक के कमरों में बेड और अन्य चिकित्सा उपकरण भी मिले, जिन्हें जांच के लिए जप्त किया गया है। वहीं, क्लीनिक में गर्भपात से संबंधित गतिविधियों की आशंका को लेकर भी जांच की जा रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बरामद सामग्री सहित पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि इस क्लीनिक को लेकर पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी। समझाइश के बाद कार्रवाई समाप्त की गई थी। इसके बाद साई मंगलम कॉलोनी में प्रकाश गुप्ता के मकान को किराए पर लेकर दोबारा कथित रूप से अवैध क्लीनिक संचालित किए जाने की जानकारी सामने आने पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए पंचनामा एवं जप्ती के बाद अवैध क्लीनिक को सील कर दिया है। साथ ही जल्द एफआईआर कराने की बात की जा रही है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सुमित गुप्ता, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अर्शिया खान, वीरेन्द्र मेहरा, सहित स्वास्थ विभाग का अमला मौजूद रहा।

भारत ने दुनिया में बनाई अपनी नई पहचानः राकेश सिंह

जबलपुर (स्वतंत्र मत)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कार्यकाल देश के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायी रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी नई पहचान और मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित की है। यह बात लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने पश्चिम विधानसभा के महर्षि वाल्मीकि मंडल की मंडल कार्यसमिति बैठक में रामपुर में कही। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम विधानसभा के महर्षि वाल्मीकि मंडल, केंट विधानसभा के अटल बिहारी बाजपेई मंडल, वीर सावरकर मंडल, शहीद भगत सिंह मंडल, छत्र पति शिवाजी मंडल, पूर्व विधानसभा के तिलक मंडल, मुखर्जी मंडल एवं उत्तर विधानसभा के विवेकानंद मंडल में कार्यसमिति का आयोजन किया गया। मंडल कार्यसमिति में मंत्री श्री सिंह ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों को पक्के आवास, करोड़ों परिवारों तक नल से जल, उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति, आयुष्मान भारत के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा, जनधन खातों के माध्यम से आर्थिक समावेशन, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और महिलाओं के सशक्तिकरण सहित अनेक योजनाओं के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सुविधा पहुंचाने का कार्य किया है।

सिहोरा पुलिस थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

आगामी त्योहारों को देखते हुऐ सिहोरा पुलिस थाना परिसर में बुधवार शाम 6 बजे शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओपी आदित्य सिंघारिया, मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष संध्या दिलीप दुबे, नगर पालिका अधिकारी प्रदीप झरिया, तहसीलदार सुमित गुप्ता, थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को द्वारा की गई। बैठक में एसडीओपी ने शांति समिति के सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराया उन्होंने कहा की क्षेत्र में शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी त्योहार आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाए जाएं इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें उन्होंने यह भी बताया की असामाजिक तत्वों और हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीजे के उपयोग में निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करने तथा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करने की भी हिदायत दी।

परियोजना प्रबंधक से महिला कर्मी के पति ने की जमकर मारपीट

जिला पंचायत कार्यालय का मामला, एफआईआर दर्ज

जबलपुर (स्वतंत्र मत)

जिला पंचायत कार्यालय में परियोजना प्रबंधक अंजुला झा से मारपीट का एक वीडियो सामने सामने आया है। बताया जा रहा है कि जब वह दफ्तर में काम कर रही थीं, तभी दोपहर के समय सहायक विकासखंड प्रबंधक आरती सोनी के पति योगेश सोनी वहां पहुंच गए। वे अपशब्द कहते हुए अंजुला झा के पास गए और अपनी कुर्सी पर बैठी महिला अधिकारी को थप्पड़ मारने लगे। बीच-बचाव करने पहुंचे साथी कर्मचारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान योगेश सोनी ने महिला अधिकारी को लात भी मार दी। अब इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

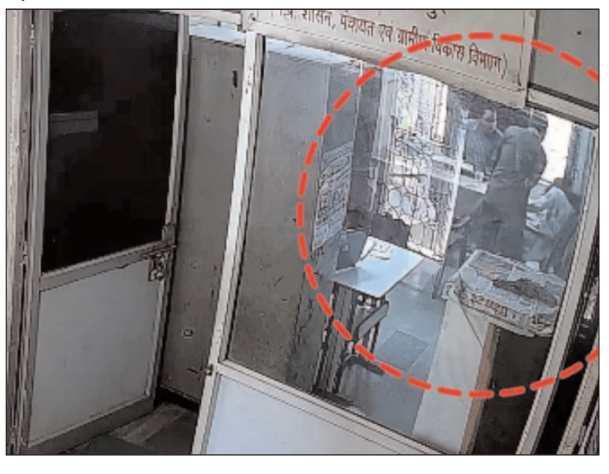

ये है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक अंजुला झा एक मामले में आरती सोनी के खिलाफ विभागीय जांच कर रही हैं। इसी जांच से नाराज होकर योगेश सोनी ने कार्यालय पहुंचकर मारपीट की। जिला पंचायत में परियोजना प्रबंधक अंजुला झा ने पुलिस को बताया कि सहायक विकासखंड प्रबंधक आरती सोनी के पति योगेश सोनी अचानक उनके कार्यालय में घुस आए। उन्होंने अभद्रता की और शासकीय काम में बाधा डाली। अंजुला झा के मुताबिक, यह हमला उनके द्वारा की जा रही विभागीय जांच की रंजिश में किया गया है।

कार्यालय में मचा हड़कंप

घटना के बाद जिला पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। अचानक हुए घटनाक्रम से अधिकारी-कर्मचारी सकते में आ गए। हालांकि, पूरे मामले में सहायक विकासखंड प्रबंधक आरती सोनी से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। वहीं, उनके पति घटनाक्रम के बाद फरार हो गए। इस मामले में थाना प्रभारी जितेंद्र पाटकर ने बताया कि अंजुला झा की लिखित शिकायत पर योगेश सोनी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

हितकारिणी प्रकाशन प्रायवेट लिमिटेड के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक- राम असरानी** द्वारा प्रेस काम्पलेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस, सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. **प्रबंध सम्पादक- सुबोध दुबे, सम्पादक- राजेन्द्र मिश्रा,** *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयनार्थ उत्तरदायी। ई-मेल-**smatjbp1@gmail.com**, फोन- 0761-2411414, 4032436 समस्त विवाद जबलपुर न्यायालयाधीन. पोस्टल रजि. नं. एसएसपी जबलपुर/13/2026-28, **RNI No. 64561/96.**